पेरिस ओलंपिक 2024 की बुधवार यानी 24 जुलाई को फुटबॉल और रग्बी मैच के साथ शुरुआत हुई। खेलों के महाकुंभ का फैंस को जितना इतंजार था, उस हिसाब से खेलों की शुरुआद विवाद के साथ हुई।

जनहितैषी

हिन्दी दैनिक

जनहितैषी अब janhitaishinews.com पर भी

R.N.I. No. 64278/96 वर्ष:29 अंक: 84 दिनांक:27-07-2024 शनिवार मूल्य : 1 रूपया 50 पैसा पृष्ठ:4 वडोदरा M

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी मानहानि के एक मामले में सुल्तानपुर की अदालत में पेश होने आए थे। राहुल गांधी सुल्तानपुर शहर के बाहरी इलाके में एक मोची की दुकान पर रुके और उसका हालचाल जाना।

मुंबई में भारी बारिश....पुलिस की लोगों को सलाह घर पर ही रहे

मौसम विज्ञान विभाग ने शनिवार तक के लिए रेड अलर्ट जारी किया

मुंबई (ईएमएस)। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में भारी बारिश के पूर्वानुमान के बाद पुलिस ने मुंबई निवासियों को शनिवार सुबह 8:30 बजे तक घर के अंदर ही रहने की सलाह दी है। यह सलाह भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) द्वारा जारी रेड अलर्ट के बाद है। पिछले 24 घंटों में शुक्रवार सुबह 8:30 बजे तक मुंबई शहर में 44 मिमी, पूर्वी उपनगरों में 90 मिमी और पश्चिमी उपनगरों में 89 मिमी बारिश दर्ज की गई। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने स्थिति का आकलन कर रायगढ़ कलेक्टर को बाढ़ प्रभावित निवासियों की सहायता करने का निर्देश दिया। भूस्खलन के कारण रायगढ़-पुणे मार्ग पर तम्हिनी घाट पर यातायात रोक दिया गया।

पुणे में सड़कों पर और लोगों के घरों में पानी घुस गया है। खडकवासला बांध और जलग्रहण क्षेत्र में काफी बारिश हो रही है। जिला कलेक्टर, नगर आयुक्त और पुलिस आयुक्त अलर्ट पर हैं, सीएम शिंदे ने बताया कि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) और राज्य समकक्ष की टीमों को तैनात किया गया है, और सेना की एयरलिफ्टिंग टीमें स्टैंडबाय पर हैं।

सार्वजनिक सुरक्षा संदेश

मुंबई पुलिस ने पोस्ट किया, आईएमडी ने कल सुबह 8:30 बजे तक मुंबई के लिए रेड अलर्ट घोषित किया है। सभी मुंबईवासियों से अनुरोध है कि जब तक जरूरी न हो, घर के अंदर ही रहें। कृपया सुरक्षित रहें। आपात स्थिति के लिए 100, 112 डायल करें।

रनवे परिचालन को पहले सुबह 8:32 बजे से सुबह 8:43 बजे तक 11 मिनट के लिए रोका गया, और फिर सुबह 10:36 बजे से 10:55 बजे तक 19 मिनट के लिए रोका गया क्योंकि दृश्यता 300 मीटर तक गिर गई और रनवे विजुअल रेंज (आरवीआर) गिर गई।

यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे एयरलाइन वेबसाइटों और सोशल मीडिया चैनलों के माध्यम से उड़ान की स्थिति के बारे में अपडेट रहें और मुंबई में चल रही भारी बारिश और यातायात की भीड़ के बीच हवाई अड्डे के लिए अतिरिक्त यात्रा समय की योजना बनाएं। मुंबई, ठाणे और पालघर में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं मौसम विभाग ने पुणे शहर और घाट इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी के लिए रेड अरल्ट जारी किया गया है। भोर, वेल्हा, मावल, मुलशी, खड़कवासला, हवेली, खेड़, अम्बेगांव, जुन्नार, पुणे शहर और पिंपरी चिंचवाड़ में सभी आंगनवाड़ी, स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। ट्रेनें, बस, फ्लाइट्स समेत तमाम ट्रांसपोर्ट बाधित हुए हैं। लोगों को घरों में ही रहने को कहा गया है। रायगड के लिए 'रेड अलर्ट' जारी किया गया है। महाराष्ट्र में चार नदियां भी खतरे के निशान को पार कर गई हैं। राहत कार्य के लिए महाराष्ट्र में आर्मी को लगाया गया है।

एशिया कप के फाइनल में टीम इंडिया

दांबुला / श्रीलंका(ईएमएस)। भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए वूमेन्स एशिया कप 2024 के फाइनल में जगह बना ली है। शुक्रवार को रंगिरि दांबुला इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए पहले सेमीफाइनल मुकाबले में भारत ने बांग्लादेश को 10 विकेट से करारी शिकस्त दी। इस मुकाबले में भारत को जीत के लिए महज 81 रनों का टारगेट मिला था, जिसे उसने 11 ओवर में ही हासिल कर लिया। फाइनल में भारतीय टीम का सामना श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच होने वाले दूसरे सेमीफाइनल मैच के विजेता से होगा। टूर्नामेंट का फाइनल 28 जुलाई को खेला जाएगा।

भारत के लिए ओपनर बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने 39 गेंदों पर नाबाद 55 रन बनाए, जिसमें 9 चौके के अलावा एक सिक्स शामिल रहा। वहीं शेफाली वर्मा 26 रन पर नाबाद रहीं। शेफाली ने 28 गेंदों की पारी में 2 चौके लगाए। इन दोनों ने धांसू बल्लेबाजी करके बांग्लादेश को मैच में वापसी का कोई मौका नहीं दिया। इससे पहले टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी बांग्लादेश की टीम निर्धारित 20 ओवरों में 8 विकेट पर 80 रन ही बना सकी। बांग्लादेश के लिए कप्तान निगार सुल्ताना ने सबसे ज्यादा 32 रन बनाए। इसके अलावा शोर्ना अख्तर (नाबाद 19 रन) ही दोहरे अंकों में पहुंच सकी। भारत की ओर से तेज गेंदबाज रेणुका सिंह और स्पिनर राधा यादव ने तीन-तीन विकेट लिए। जबकि पूजा वस्त्राकर और दीप्ति शर्मा को एक-एक सफलता मिली।

दिल्ली में भाजपा और संघ के प्रमुख नेताओं के बीच बैठक -योगी आदित्यनाथ के भाग्य का होगा फैसला

उत्तर प्रदेश के संगठन और सत्ता में बड़े फेरबदल की तैयारी

नई दिल्ली (ईएमएस)। भाजपा में इन दिनों उत्तर प्रदेश को लेकर बड़ी हलचल मची हुई है।पिछले कई दिनों से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और बृजेश पाठक के बीच में लगातार मतभेद की खबरें बाहर आ रही हैं। मुख्यमंत्री द्वारा बुलाई गई बैठक में दोनों मुख्यमंत्री शामिल नहीं हो रहे हैं। तीनों के बीच मतभेद की खबर सुर्खियों में है। मीडिया में कहा जा रहा है, केंद्रीय नेतृत्व उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बदलना चाहता है। दोनों उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और बृजेश पाठक केंद्रीय नेतृत्व के इशारे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, नीति आयोग की बैठक में भाग लेने के लिए दिल्ली पहुंचे हैं। कल भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों की एक बैठक बुलाई है। संघ प्रमुख मोहन भागवत भी दिल्ली में हैं।कहा जा रहा है, कल एक उच्च स्तरीय बैठक दिल्ली में होने जा रही है। जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, संघ प्रमुख मोहन भागवत, गृहमंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तथा दोनों उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और बृजेश पाठक इस बैठक में शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश की सत्ता और संगठन के बारे में महत्वपूर्ण निर्णय की संभावना जताई जा रही है। इसको लेकर दिल्ली का राजनीतिक माहौल काफी गर्म है। बड़ी संख्या में भाजपा के उत्तर प्रदेश के विधायक दिल्ली पहुंचे हुए हैं। भाजपा के अंदर उत्तर प्रदेश की सत्ता और संगठन को लेकर जो तूफान पार्टी के अंदर मचा हुआ है। उसको देखते हुए समाजवादी पार्टी भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय हो गई है। कहा जा रहा है, भाजपा के बहुत सारे विधायक बगावत की मुद्रा में है। ऐसी स्थिति में भाजपा हाईकमान के लिए उत्तर प्रदेश का मामला सुलझाने की सर्वोच्च प्राथमिकता में है। शनिवार को इस मामले में कोई बड़ा निर्णय भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व ले सकता है। संघ प्रमुख मोहन भागवत के दिल्ली पहुंचने के बाद इस मामले की गंभीरता का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। यह कहा जा रहा है, एक-दो दिन के अंदर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में भाजपा हाईकमान कोई बड़ा फैसला लेने जा रहा है। भाजपा हाईकमान और संघ इस मामले में भी चर्चा कर रहा है। यदि योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटाया जाता है। तो इसका असर हरियाणा झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव में किस तरह से पड़ेगा। इसका भी आकलन किया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व के एक बड़े चेहरे हैं।

कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ पर पीएम मोदी बोले अग्निवीर पर झूठ फैला रहा विपक्ष

द्रास (ईएमएस)। कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ पर शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लद्दाख में 1विनोद उपाध्याय / 26 जुलाई, 2024 की जंग के नायकों को श्रद्धांजलि दी। वे कारगिल वॉर मेमोरियल भी गए। करीब 20 मिनट के संबोधन में पीएम ने पाकिस्तान, आतंकवाद, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, अग्निपथ योजना और विपक्ष पर बात की। पीएम ने कहा कि पाकिस्तान प्रॉक्सी वॉर के जरिए चर्चा में बना रहना चाहता है। उन्होंने अपने इतिहास से कुछ नहीं सीखा। अतीत में आतंकवाद को लेकर उनके हर प्रयास विफल रहे। मैं जहां खड़ा हूं, वहां से आतंक के आकाओं तक मेरी आवाज पहुंच रही होगी। उनके मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे।

प्रधानमंत्री ने कहा कि सेना का रिफॉम्र्स हमारी पहली प्राथमिकता है। अग्निपथ योजना इसका हिस्सा है। संसद में दशकों तक सेना को युवा बनाने पर चर्चा होती रहीं। कई कमेटियों में ये विषय उठा, लेकिन इस बदलाव की पहले इच्छा शक्ति नहीं दिखाई गई। कुछ लोगों की मानसिकता यही थी कि सेना मतलब नेताओं को सलाम करना, परेड करना। हमारे लिए सेना मतलब 140 करोड़ देशवासियों की सुरक्षा, शांति की गारंटी। अग्निपथ योजना के जरिए इसे हमने साकार किया है। दुर्भाग्य से इतने संवेदनशील विषय को कुछ लोगों ने राजनीति का विषय बना दिया है।

टनल की आधारशिला रखी

प्रधानमंत्री मोदी ने कारगिल वॉर मेमोरियल पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद लद्दाख में शिंकुन ला टनल प्रोजेक्ट के लिए पहला वर्चुअल ब्लास्ट किया। यह दुनिया की सबसे ऊंचाई पर बनने वाली टनल है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई करीब 15,800 फीट है। यह हिमाचल प्रदेश की लाहौल वैली को लद्दाख की जास्कर वैली से जोड़ेगी। 4.1 किमी लंबी यह टनल निमू-पदुम-दारचा रोड पर बनाई जाएगी। इसे बनाने में करीब 1681 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। सीमा सडक़ संगठन (बीआरओ) करीब दो साल में बनाकर तैयार करेगा। इलाके में साल के चार-पांच महीने बर्फ जमी रहती है। टनल बन जाने के बाद यहां सालभर आवाजाही की जा सकेगी। शिंकुन ला टनल एक ट्विन-टयूब डबल लेन टनल होगी। इसमें हर 500 मीटर के बाद क्रॉस पैसेज होंगे। इसके अंदर सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन सिस्टम, मैकेनिकल वेंटिलेशन सिस्टम, फायर फाइटिंग सिस्टम और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जैसी सुविधाएं होंगी।

अग्निपथ योजना पर खुलेआम झूठ बोल रहे पीएम मोदी : खड़गे

पूर्व सेना प्रमुख जनरल नरवणे के बयान का ज़िक्र

नई दिल्ली (ईएमएस)। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कारगिल विजय दिवस पर ओछी राजनीति करने का आरोप लगाया। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे की आलोचना पीएम मोदी द्वारा द्रास में एक संबोधन के दौरान अग्निपथ योजना की आलोचना के लिए विपक्ष पर निशाना साधकर सेना को कमजोर करने का प्रयास करने का आरोप लगाने के कुछ घंटों बाद आई है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है कि प्रधानमंत्री मोदी जी कारगिल विजय दिवस पर शहीदों को श्रद्धांजलि देने जैसे अवसरों पर भी तुच्छ राजनीति कर रहे हैं।

खरगे ने कहा कि पीएम मोदी का दावा कि उनकी सरकार ने सेना के आदेश पर अग्निपथ योजना लागू सरासर झूठ और हमारे बहादुर सशस्त्र बलों का अक्षम्य अपमान है। खरगे ने कहा कि मोदी जी, आप ही हैं जो झूठ फैला रहे हैं! पूर्व सेना प्रमुख (सेवानिवृत्त) जनरल एमएम नरवणे ने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि अग्निपथ योजना में 75 प्रमतिशत भर्तियों को स्थायित्व के लिए लिया जाना था और 25 प्रतिशत लोगों को 4 साल बाद जाने दिया जाना था। लेकिन मोदी सरकार ने इसका उलटा कर योजना को तीनों सशस्त्र बलों के लिए जबरन लागू कर दिया।

उन्होंने कहा कि पूर्व सेना प्रमुख (सेवानिवृत्त) जनरल नरवणे ने अपनी पुस्तक में, इस मोदी सरकार ने प्रकाशित होने से रोक दिया है, कहा है कि अग्निपथ योजना सेना और नौसेना और वायु सेना के लिए चौंकाने वाली थी।

सात लाख अदालती मामलों में केंद्र सरकार पक्षकार ,वित्त, रेलवे और रक्षा से संबंधित सबसे ज्यादा मामले

नई दिल्ली (ईएमएस)। केंद्रीय कानून राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने राज्यसभा में बताया कि केंद्र करीब सात लाख अदालती मामलों में पक्षकार है। इसमें रक्षा, रेलवे और वित्त मंत्रालय के मामले 50 प्रतिशत से अधिक हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक, राज्यसभा में मंत्री मेघवाल द्वारा दिए आंकड़ों के अनुसार, सरकारी मंत्रालयों से जुड़े कुल 6,98,904 मामले अदालतों में लंबित हैं, जिसमें केंद्रीय मंत्रालय और विभाग पक्षकार हैं। इन मामलों में सबसे अधिक 57 प्रतिशत मामले तीन मंत्रालयों वित्त, रेलवे और रक्षा से संबंधित हैं।

हालांकि, उन्होंने कानून मंत्रालय के कानूनी सूचना प्रबंधन और ब्रीफिंग सिस्टम (एलआईएमबीएस) के डेटा की सहायता से आंकड़ें पेश किए, इसपर सभी मंत्रालय अपने स्वयं के मामलों का विवरण दर्ज़ करते हैं।

एलआईएमबीएस डेटा के अनुसार, 19 जुलाई तक कुल 6,98,904 मामले अदालतों में लंबित थे, जिसमें केंद्र सरकार एक पक्षकार थी। इसमें सबसे अधिक लंबित मामले वित्त मंत्रालय से जुड़ा हैं, जिनकी संख्या 1,89,289 है। इसके बाद रेलवे का नंबर आता है, जिसके 1,14,557 मामले लंबित है। वहीं, रक्षा के भी 95,467 मुकदमे लंबित हैं।इनके अलावा श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के 79,988 मामले और गृह मंत्रालय के 24,409 मामले लंबित हैं। विभिन्न हाईकोर्ट में कुल 2,53,073 मामले लंबित हैं। लंबित मामलों की संख्या सुप्रीम कोर्ट में 17,779 है।

कांग्रेस का मोहरा बन चुके हैं अखिलेश यादव: केशव प्रसाद मौर्य

लखनऊ (ईएमएस)। सपा प्रमुख और पूर्व सीएम अखिलेश यादव के मोहरा बताए जाने के बाद अब उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ने भी पलटवार किया है। केशव प्रसाद मौर्य ने पोस्ट कर कहा कि कांग्रेस का मोहरा बन चुके सपा बहादुर अखिलेश जी भाजपा को लेकर गलतफहमी पालने, अति पिछड़ों को निशाना बनाने, अपमान करने की जगह सपा को समाप्त होने से बचाने पर ध्यान दें। भाजपा 2027 में 2017 दोहराएगी, कमल खिला है खिलेगा,खिलता रहेगा। दरअसल, कपिल सिब्बल को दिए इंटरव्यू में अखिलेश ने योगी और केशव प्रसाद मौर्य के बीच खींचतान की खबरों पर कहा था कि बीजेपी में झगड़ा दो नेताओं के बीच नहीं, बल्कि दिल्ली और लखनऊ के बीच है। अखिलेश ने कहा कि केशव प्रसाद सिर्फ मोहरा हैं।

संसद में किसानों के मुद्दे पर प्रश्नकाल के दौरान जोरदार हंगामा

नई दिल्ली(ईएमएस)। राज्यसभा में किसानों के मुद्दे पर प्रश्नकाल के दौरान जोरदार हंगामा हुआ। प्रश्नकाल के दौरान समाजवादी पार्टी (सपा) के सांसद रामजी लाल सुमन ने 12 जुलाई 2000 को किसानों की समस्याओं पर बनी कमेटी की बैठकों के ब्यौरे को लेकर सवाल किया। इसके जवाब में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसान हमारे लिए भगवान की तरह है और किसान की सेवा हमारे लिए पूजा जैसी है। उन्होंने कहा कि इस समिति का गठन तीन उद्देश्यों- एमएसपी उपलब्ध कराने और व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के साथ कृषि मूल्य को अधिक स्वायत्तता और कृषि वितरण प्रणाली के लिए सुझाव देने के लिए। उचित दाम देने के लिए समिति की रिपोर्ट आएगी तब हम कार्रवाई करेंगे।

कृषि मंत्री ने कहा कि समिति की 22 बैठकें हो चुकी हैं। समिति जो सिफारिश देगी, उस पर विचार किया जाएगा। इस पर रामजी लाल सुमन ने कहा कि ये अनिश्चितता का वातावरण है। ये कब दूर होगा। ये जो किसान को भगवान बता रहे हैं, इनको किसानों से कोई लेना-देना नहीं है। सीधा जवाब दीजिए कि आप एमएसपी को कानूनी दर्जा देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते। बचिए मत। इसके बाद सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि राम, शिव से सवाल पूछ रहे हैं। जवाब में शिवराज ने कहा कि एमएसपी की दरें किसान को ठीक दाम देने के लिए लगातार बढ़ाई गई है। ये गलत आरोप लगा रहे हैं।

सरकार की छह सूत्रीय रणनीति

कृषि मंत्री ने कहा की कृषि के लिए सरकार की छह सूत्रीय रणनीति है। शिवराज ने उत्पादन बढ़ाने से लेकर लागत घटाने तक के उपाय गिनाए और कहा कि हमें किसान विरोधी कहा जा रहा है। नरेंद्र मोदीजी से बड़ा किसान हितैषी कोई है नहीं। उचित दाम देने के लिए समिति की रिपोर्ट आएगी तब हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन तब तक हम चुप नहीं बैठे हैं। उन्होंने फसलों के एमएसपी के दाम बढ़ाए जाने के आंकड़े गिनाए और कहा कि इन 23 फसलों के दाम देख लीजिए। इस दौरान विपक्ष के सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। शिवराज ने कहा कि जब सुरजेवालाजी की सरकार हुआ करती थी, उससे दोगुने एमएसपी दिए हैं नरेंद्र मोदी की सरकार ने। हम किसान के हित में लगातार फैसले लेते जा रहे हैं।उन्होंने किसानों के लिए सम्मान निधि के साथ ही गेहूं-धान की खरीद बढऩे का भी जिक्र किया। शिवराज ने कहा कि सरकार फर्टिलाइजर पर 1 लाख 68 हजार करोड़ रुपये की सब्सिडी दे रही है। और भी कदम जरूरी हैं जिन्हें लेकर सरकार गंभीर है। इसके बाद रणदीप सुरजेवाला और विपक्ष के अन्य सांसदों ने एमएसपी की लीगल गारंटी को लेकर हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के बीच सभापति ने दोनों पक्ष के सदस्यों से बैठने के लिए कहा और नेम करने की चेतावनी दी। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि तुअर, मसूर, उड़द किसान जितना उत्पादन करेगा, ये सरकार खरीदेगी।

विपक्ष घड़ियाली आंसू बहा रहा

कृषि मंत्री ने यूपीए और एनडीए सरकार के कार्यकाल में एमएसपी पर हुई खरीद के आंकड़े गिनाए और कहा कि ये घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। इस पर सप्लीमेंट्री की मांग को लेकर विपक्ष के हंगामे पर सभापति ने कहा कि सप्लीमेंट्री गन की नोक पर लोगे, ऐसे नहीं होगा। उन्होंने कहा कि बच्चे की तरह जिद क्यों कर रहे हो रणदीप, नो। शिवराज ने यूपीए सरकार का कैबिनेट नोट भी टेबल पर रखा जिसमें लागत पर 50 फीसदी बढ़ाकर एमएसपी निर्धारित करने से इनकार की बात कही गई थी। उन्होंने स्वामीनाथन समिति की सिफारिशें लागू करने से इनकार का भी उल्लेख किया। इस दौरान विपक्ष के सदस्यों ने जोरदार हंगामा किया। उन्होंने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि ये किसान के नाम पर केवल राजनीति करना चाहते हैं, देश को अराजकता में झोंकना चाहते हैं। पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, किसान की बेहतरी के लिए काम करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।

सपा का दावा - मनोज पांडेय बनेंगे यूपी की भाजपा सरकार में उप मुख्यमंत्री

नई दिल्ली (ईएमएस)। समाजवादी पार्टी ने दावा किया है कि मनोज पांडेय, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं। यूपी में राज्यसभा चुनाव के दौरान मनोज पांडेय ने सपा से बगावत कर बीजेपी का रुख कर लिया था। वे रायबरेली स्थित ऊंचाहार से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़कर विधानसभा पहुंचे थे।

सपा नेता आईपी सिंह ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा- राजनैतिक हलकों में चर्चा है कि मनोज पांडेय की भाजपा से जो डील हुई उन्हें उप-मुख्यमंत्री बनाया जायेगा। ब्रजेश पाठक बसपा से भाजपा में 2017 में गये और मनोज पांडेय ने 2024 में सपा से भाजपा में शामिल हुए हैं।

सपा नेता ने लिखा कि- ब्रजेश पाठक केशव गैंग के सदस्य के रूप में योगी जी को हटाने की मुहिम का हिस्सा हैं। जानकारी जो दिल्ली से आ रही है दोनों उप मुख्यमंत्री गुजरात और बिहार के तर्ज पर हटाये जा सकते हैं। पाठक ने भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉ। दिनेश शर्मा को निबटा कर कुर्सी हासिल की अब मनोज पांडेय इन्हें निबटाने जा रहे हैं। ये रस्साकशी बीजेपी को पाताल में ले जायेगी।

डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और बीजेपी नेता मनोज पांडेय के मुलाकात की एक एक्स पोस्ट पर जवाब देते हुए आईपी सिंह ने यह दावा किया। गुरुवार को ही ब्रजेश और मनोज की मुलाकात हुई थी।

कांवड़ रूट में नाम लिखने पर रोक जारी रहेगी

नई दिल्ली (ईएमएस)। यूपी में कांवड़ रूट पर नाम लिखने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट की अंतरिम रोक जारी रहेगी। कोर्ट ने शुक्रवार को यूपी सरकार के जवाब दाखिल करने के बाद ये आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड और मध्यप्रदेश सरकार को भी अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा है।

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान यूपी सरकार के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा- केंद्रीय कानून के मुताबिक यह आदेश दिया गया है। कोर्ट बोला- सभी जगह लागू करिए। फिर वकील ने कहा- कांवड़ सिर्फ तीन राज्यों से गुजरते हैं। यह सिर्फ खाने-पीने के लिए नहीं है। केंद्रीय कानून में दी गई व्यवस्था के मुताबिक है। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। जबकि कानून में यह व्यवस्था दी गई है कि राज्य इसे लागू कर सकते हैं। मुकुल रोहतगी ने कहा- एक कांवडिए ने याचिका दाखिल करके कहा कि राज्य का आदेश उचित है। खाना क्या है यह पता होना चाहिए। मुजफ्फरनगर पुलिस की तरफ से यह निर्देश बाध्यकारी तौर पर नहीं लागू किया गया।

जम्मू-कश्मीर की तर्ज पर पश्चिम बंगाल को भी दो हिस्सों में बांटा जाएगा

नई दिल्ली (ईएमएस)। जम्मू-कश्मीर की तर्ज पर पश्चिम बंगाल को भी दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। केंद्रीय मंत्री और बंगाल भाजपा प्रमुख सुकांत मजूमदार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उनसे अनुरोध किया कि वे पश्चिम बंगाल के आठ जिलों को पूर्वोत्तर का हिस्सा मानें, जिनकी सीमाएं सिक्किम से लगती हैं।

बैठक के बाद मजूमदार ने कहा, मैंने प्रधानमंत्री को एक प्रस्ताव सौंपा है और उन्हें बताया कि आखिर क्यों उत्तर बंगाल को पूर्वोत्तर का हिस्सा माना जाना चाहिए और दोनों के बीच क्या समानताएं हैं। अगर वे मेरा प्रस्ताव स्वीकार करते हैं तो बंगाल के इस पिछड़े इलाके को केंद्र से अधिक धन मिलेगा। मेरा मानना है कि राज्य सरकार सहयोग करेगी।

यह एक सामान्य बैठक नहीं थी, बल्कि यह भविष्य में भाजपा द्वारा आधिकारिक तौर पर राज्य के विभाजन की मांग करने की प्रवृत्ति को दर्शाता है। सूत्रों का कहना है कि प्रधानमंत्री ने मजूमदार के साथ करीब आधे घंटे बिताए, जिससे यह पता चलता है कि वे प्रस्ताव को कितना महत्व देते हैं।

मजूमदार पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास से संबंधित मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं। ऐसे में उनका यह प्रस्ताव महत्वपूर्ण हो जाता है। वे पश्चिम बंगाल भाजपा के अध्यक्ष भी हैं, जिससे मांग का राजनीतिक महत्व बढ़ जाता है। इससे पहले मजूमदार को भाजपा सांसदों द्वारा अलग उत्तर बंगाल की कई मांगों को व्यक्तिगत राय के रूप में खारिज करना पड़ा था। दिलचस्प बात यह है कि वे बालुरघाट निर्वाचन क्षेत्र से आते हैं, जो भी उत्तर बंगाल के अंतर्गत आता है।

राहुल गांधी अचानक पहुंचे मोची की दुकान, ठीक किए पुराने जूते

सुल्तानपुर (ईएमएस)। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर कोर्ट में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ विवादास्पद टिप्पणी मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पेश हुए। सुल्तानपुर एमपी-एमएलए कोर्ट में पेश होने के बाद राहुल गांधी लखनऊ वापस लौट रहे थे। इस दौरान जब उनका काफिला कूरेभार के विधायक नगर चौराहे पर पहुंचे तो चारों तरफ हलचल मच गई। अचनाक उनका काफिला चेत राम मोची की दुकान के पास रुक गया। दुकान पर राहुल गांधी पुराने जूते को ठीक करते दिखे। उनसे बातचीत की। वहां पांच मिनट रुककर राहुल ने उनसे व्यापार के बारे में बातचीत की, सेल्फी लिया। इसके बाद उनका काफिला पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के लिए निकल गया।

रायबरेली सांसद राहुल गांधी शुक्रवार को सुल्तानपुर के एमपी-एमएलए कोर्ट में हाजिर हुए। कोर्ट रूम 16 मिनट रुककर उन्होंने अपना बयान दर्ज कराया उसके बाद उनका काफ़िला वापस लखनऊ के लिए चल पड़ा। राहुल को पूर्वांचल के रास्ते लखनऊ एयरपोर्ट जाना था। राहुल गांधी का काफ़िला सुल्तानपुर से करीब 13 किमी दूर कूरेभार के विधायक नगर चौराहे पर पहुंचा तो उन्होंने बाए हाथ पर मोची की दुकान देखते ही गाड़ी रुकवाया और उतर कर सीधे चेत राम मोची के पास पहुंचे।

राहुल गांधी का काफिला रुकते ही कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और समर्थकों की भीड़ आसपस जमा हो गई। चेत राम की गुमटी पर वे पांच मिनट रुके, बातचीत की, सेल्फी ली और फिर गंतव्य के लिए रवाना हो गए।

चेत राम मोची ने बताया कि जिस जूते को हम सील रहे थे, राहुल ने उसे छूकर देखा। उन्होंने पूछा कि कैसे बनाते हैं। उन्होंने ये भी जाना कि घर का भरण-पोषण कैसे चलता है। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से मुलाकात पर मोची चेत राम ने खुशी जताई। उन्होंने कहा कि हमने उनसे (राहुल गांधी) बोला है कि मैं पूंजी से कमजोर हूं, गरीब हूं। हमारी थोड़ी मदद कीजिए। मैंने उन्हें जूतों की सिलाई करके दिखाया। राहुल गांधी ने भी उसे छुआ।

विधेयकों को मंजूरी देने से इनकार का मामला: केंद्र, बंगाल-केरल के राज्यपालों से मांगा जवाब

नई दिल्ली (ईएमएस)। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र सरकार, पश्चिम बंगाल और केरल के राज्यपालों के सचिवों से विधेयकों को मंजूरी न देने के मुद्दे पर जवाब मांगा है। राज्य सरकारों ने इस मामले में याचिका दायर की थी, इन्हीं याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने केंद्रीय गृह मंत्रालय और दोनों राज्यपालों के सचिवों को नोटिस जारी किए। केरल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील केके वेणुगोपाल ने कहा कि वे विधेयकों को राष्ट्रपति के विचारार्थ भेजने के राज्यपाल के फैसले को चुनौती दे रहे हैं।

पश्चिम बंगाल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी और जयदीप गुप्ता ने कहा कि जब भी मामला सुप्रीम कोर्ट में सूचीबद्ध होता है, राज्यपाल कार्यालय विधेयकों को राष्ट्रपति के पास भेज देता है। राज्य सरकारों ने राज्यपालों द्वारा कई विधेयकों को मंजूरी देने में की जा रही कथित देरी पर चिंता जताई। यह विवाद राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों को राज्यपाल द्वारा मंजूरी न दिए जाने से जुड़ा है। राज्य सरकारों का आरोप है कि राज्यपाल इन विधेयकों पर अपनी सहमति नहीं दे रहे हैं, जिससे जनता को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से लाए गए अहम विधायी उपायों में देरी हो रही है। राज्य सरकारों की याचिका पर ही सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल कार्यालयों और केंद्र को नोटिस जारी किया है।

संविधान हत्या दिवस के खिलाफ याचिका खारिज

नई दिल्ली (ईएमएस)। दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को संविधान हत्या दिवस के विरोध में दायर जनहित याचिका खारिज कर दी। केंद्र सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित किया था। गृह मंत्री अमित शाह ने 12 जुलाई को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी थी। अगले दिन 13 जुलाई को सरकार ने नोटिफिकेशन भी जारी किया था। सरकार ने इसे इंदिरा गांधी सरकार द्वारा 1975 में लगाई गई इमरजेंसी के खिलाफ लडऩे वाले लोगों के लिए श्रद्धांजलि बताया था। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस तुषार राव गेडेला की बेंच ने फैसला सुनाते हुए कि अधिसूचना आर्टिकल 352 के तहत इमरजेंसी की घोषणा के खिलाफ नहीं, बल्कि सत्ता और संवैधानिक प्रावधानों के दुरुपयोग के खिलाफ है।

दुनिया की 73.3 करोड़ आबादी खाली पेट सोने को मजबूर

पिछले 5 वर्षों में 233 करोड लोग कुपोषण के शिकार

जिनेवा (ईएमएस)। संयुक्त राष्ट्र संघ की पांच एजेंसियों द्वारा रिपोर्ट जारी की गई है। द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन 2024 की रिपोर्ट में विश्व खाद्य सुरक्षा की स्थिति पर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। कॉविड-19 के पहले जो स्थिति थी। उससे भयावह स्थिति में 2024 मे हो गई है।

रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में हर 11 इंसान मे 1 इंसान खाली पेट सोने के लिए मजबूर हो गया है। द

जन हितैषी

खनिजों पर टैक्स लगाने का अधिकार मिला राज्यों को

सुप्रीम कोर्ट की 9 सदस्य वाली खंडपीठ ने 8+1 से फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने इस फैसले में स्पष्ट किया गया है। रॉयल्टी, टैक्स के दायरे में नहीं आती है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्व के एक फैसले में कहा था, कि रॉयल्टी भी एक टैक्स है। जिसे 09 सदस्यों की संवैधानिक खंडपीठ ने सही नहीं माना है। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक खंडपीठ ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है, कि सरकार को जो भी भुगतान किया जाता है उसे टैक्स नहीं माना जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक खंडपीठ ने गुरुवार को जो फैसला दिया है, उसके अनुसार संविधान ने खनिज और खदानों से निकलने वाले उत्पाद और खनिज भूमि पर राज्य सरकारों के अधिकार को माना है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया है, कि राज्यों को रॉयल्टी वसूल करने का संवैधानिक अधिकार है। रॉयल्टी को टैक्स नहीं माना जा सकता है। नौ जजों की संविधान पीठ ने इस मामले की सुनवाई की थी। इसमें एक जज बीवी नगरत्ना का फैसला अलग था। उनके फैसले में यह कहा गया है, कि राज्यों को खदानों और खनिज वाली भूमि पर टैक्स लगाने का अधिकार नहीं है। वहीं आठ जजों का फैसला है, कि राज्यों का यह संवैधानिक अधिकार है। आठ जजों ने अपने फैसले में स्पष्ट किया है, कि संविधान की सूची 2 की प्रविष्टि 50 के अनुसार संसद के पास खनिज अधिकारों पर टैक्स लगाने का अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से अब स्पष्ट हो गया है कि रॉयल्टी को टैक्स के दायरे के अंतर्गत नहीं लाया जा सकता है। खनिज भूमि और खनिज उत्पाद पर राज्य सरकारों का अधिकार है। रॉयल्टी एक अधिकार है। रॉयल्टी पर सरकार, पट्टेदाता और जमीन मालिक का अधिकार होता है। इस भुगतान को टैक्स के दायरे में नहीं रखा जा सकता है। संविधान पीठ के नौ जजों की पीठ ने इस विवादास्पद मुद्दे पर केंद्र एवं राज्य सरकारों का पक्ष काफी सूक्ष्मता के साथ सुना। कई दिनों तक सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई होती रही। इसमें विवाद का विषय रॉयल्टी और खनिज भूमि केंद्र एवं राज्य के अधिकार को लेकर सुनवाई हो रही थी। खनिज अधिनियम 1957 के तहत टैक्स और रॉयल्टी की व्याख्या सुप्रीम कोर्ट को करनी थी। देश की सभी खनिज भूमि पर राज्य सरकारों का अधिकार है। राज्य सरकारों को इस मामले में रॉयल्टी वसूल करने का भी अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से यह स्पष्ट हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से सबसे ज्यादा फायदा राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल जैसे उन राज्यों को होगा, जहां बड़ी मात्रा में खनिज सम्पदा उपलब्ध है। इस फैसले के बाद राज्यों को कानून बनाने और खनिज उत्पाद पर रॉयल्टी वसूल करने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में अभी यह सुनवाई चल रही है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट को यह फैसला देना है, कि यह अधिकार राज्यों को कब से प्राप्त होगा। राज्यों द्वारा पूर्ववर्ती समय से रॉयल्टी वसूल करने की मांग की जा रही थी। सुप्रीम कोर्ट को यह निर्णय देना है, कि सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय भूतलक्षी होगा या भविष्य में लागू होगा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से राज्यों का आर्थिक आधार मजबूत होगा। केंद्र एवं राज्यों के रिश्ते भी मजबूत होंगे। इसके साथ ही रॉयल्टी और टैक्स की जो परिभाषा दी गई है, इसका असर केंद्र एवं राज्य सरकारों के साथ-साथ निजी अधिकारों के लिए भी सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला बड़ा महत्वपूर्ण साबित होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस विवाद पर लंबे समय तक सुनवाई करके संविधान और विभिन्न कानून के हर पहलुओं पर विचार किया है। इस सुनवाई में केंद्र एवं राज्य सरकारों के अधिकार को लेकर भी गहन सुनवाई है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से खनिज मामलों को लेकर जो विवाद केंद्र एवं राज्य सरकारों के बीच में चले आ रहे थे, इसमें केंद्र एवं राज्य सरकारों के अलावा निजी भूमि के मालिक भी शामिल होते थे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से अब बहुत सारे विवाद निपट जाएंगे।

छद्म एवं पाखण्डी बाबाओं से मुक्ति की सार्थक पहल

भारतीय हिंदू संतों की प्रमुख संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद (एबीएपी) की ओर से चौदह महामण्डलेश्वरों और संतों के निष्कासन की ताजा कार्रवाई पाखण्डी एवं छद्म बाबाओं से समाज को मुक्त करने का सराहनीय कदम है। अखाड़ा परिषद की गोपनीय जांच में अखाड़ों से जुड़े ये संत धार्मिक कार्यों के बजाय धनार्जन एवं अधार्मिक कार्यों में लिप्त पाए गए। ऐसे ही अन्य बाबाओं पर व्यभिचार, दुष्कर्म, जादू-टोटके व दूसरे अनैतिक कार्यों के भी आरोप लगते रहे हैं। इनके अलावा सौ से अधिक संतों को अखाड़ा परिषद ने नोटिस भी दिया है। निष्कासित किए गए संतों को अगले साल होने वाले कुंभ में भी प्रवेश नहीं मिलेगा। अखाड़ा परिषद की ताजा कार्रवाई इस तरह के कथित धर्मगुरुओं पर लगाम लगाने की प्रभावी कोशिश मानी जाएगी। इस तरह के प्रयास हर स्तर पर होने चाहिए, ताकि छद्म एवं पाखण्डी धर्मगुरुओं से समाज को मुक्ति मिल सके। आम लोगों में भी विवेक का जागरण जरूरी है, ताकि धर्म को विकृत करने वाली ऐसी घटनाओं को नियंत्रित किया जा सके।

अखाड़ा परिषद ने कुल चौदह ढोंगी संतों की एक सूची मीडिया में जारी की है। सूची में जेल की हवा खा रहे बाबा रामपाल, गुरमीत राम रहीम सिंह इंसां, आसाराम, नारायण साईं व असीमानंद के अलावा निर्मल बाबा, राधे मां और कई ऐसे इच्छाधारी बाबा शामिल हैं, जो पिछले कुछ सालों में अपनी करनी के चलते विवादों में रहे हैं। गोलगप्पा खिलाकर लोगों की हर समस्या का समाधान करने वाले निर्मल बाबा जैसे ढोंगियों के झांसे में लोग कैसे खिंचे चले आते हैं, इस पर भी अखाड़े की ओर से कई चौंकाने वाले तथ्य बताए गए हैं। उनका मानना है कि राधे मां और निर्मल बाबा जादू-टोटके से लोगों को अपनी ओर खींचते हैं। बाबाओं की कारस्तानियों ने सबको सकते में डाल रखा है। महिलाओं की अस्मत से खिलवाड़ करना इन बाबाओं की दिनचर्याओं में शामिल था। लाज-शर्म की वजह से कुछ महिलाएं नहीं बोलती थीं, उन्हीं का ये बाबा फायदा उठाते थे। इन बढ़ती त्रासद एवं विडम्बनापूर्ण स्थितियों के खिलाफ अब पूरा अखाड़ा परिषद मुखर हो उठा है। जरूरत है ऐसे ही अन्य शीर्ष धर्म संगठनों के सक्रिय होकर कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाई करने की।

फर्जी एवं पाखण्डी बाबाओं के मामले में भोले-भाले एवं अशिक्षित लोगों के जीवन के साथ जो खिलवाड़ हुआ है और जिन बाबाओं ने ये कुकर्म किया है, उन्हें ढूंढकर दंड देना ही चाहिए। फर्जी एवं पाखण्डी बाबाओं की परंपरा सदैव से दुष्टों के हाथ में रही है। इसका आरंभ किया था महाभारत में शकुनि ने। हमारे समाज एवं राष्ट्र ऐसे बहुत सारे बाबा रूपी शकुनि हैं, जिन्हें हम समय पर पहचान नहीं पाते हैं। कौरवों और पांडवों के बीच जब जुए का खेल हुआ, तो शर्त यही थी कि पांसे शकुनि चलेगा। शकुनि ने पांसे भी ऐसे तैयार किए थे कि उसको परिणाम और प्रश्न मालूम थे। आधुनिक बाबा भी ऐसे ही पांसे चलते हुए हुए कइयों की जिंदगी को नरक बना रहे हैं, कइयों के घर उजाड़ रहे हैं। सबसे ज्यादा नुकसान उन लोगों का हुआ है, जो धार्मिक आस्थाओं के प्रति अटूट विश्वास रखते थे, क्योंकि भारत की पहचान सदा से ही साधु-संतों से जुड़ी रही है। लेकिन पिछले एक-दो दशक से कुछ फर्जी बाबाओं ने अपनी काम वासना एवं धनलोलुपता के चलते सबकुछ खंडित कर दिया है। इन बाबा रूपी शकुनियों को दंड देना ही पड़ेगा। आधुनिक बाबाओं की तरह महाभारत का शकुनि कभी किसी से नहीं डरता था, लेकिन वो कहता था, दुर्योधन! मैं इस दुनिया में केवल एक ही व्यक्ति से डरता हूं और वो श्रीकृष्ण हैं। तो हमें भी आधुनिक बाबाओं के लिये श्रीकृष्ण जैसी एक सख्त व्यवस्था लागू करनी पड़ेगी। क्योंकि श्रीकृष्ण जब किसी को दंड देते थे तो अपना और पराया कभी नहीं देखते थे। श्रीकृष्ण धर्म में जय और जय में धर्म देखते थे। वर्तमान में धर्मगुरुओं एवं बाबाओं का जो चरित्र एवं आचरण प्रस्तुत हो रहा है, वह कष्टदायक एवं विनाशकारी है। इसलिये उनके लिये श्रीकृष्ण रूपी अनुशासन-व्यवस्था को सख्ती से लागू करना ही होगा।

अखाड़ा परिषद का अपना अनुशासन है। अखाड़े से जुड़े संतों में कोई दोष नहीं आ जाए, चरित्रहीनता न आ जाये, आचरण एवं जीवनशैली दूषित न हो जाये, इसे देखते हुए वह समय-समय पर अपने महामण्डलेश्वर व दूसरे संतों की कार्यप्रणाली की गोपनीय जांच कराता रहता है। ऐसी ही हाल में की गयी जांच में सामने आया कि धनार्जन में लिप्त रहने वाले संतों की कार्यप्रणाली अखाड़ों की रीति-नीति के विपरीत थी। इनमें कुछ के तो आपराधिक लोगों से भी संबंध सामने आए। राजनेताओं से भी उनके प्रगाढ़ संबंध रहे हैं। हर समुदाय में संतों का अलग ही स्थान रहता आया है। वे जहां विराजते हैं वह स्थान स्वतः ही उच्च हो जाता है। आज भी बड़ी संख्या में संत-महात्मा समाज को दिशा देने के काम में निःस्वार्थ भाव से जुटे हैं। पर बदलते दौर में संत-महात्मा-मुल्ला-मौलवियों व पीर-पगारों के छद्म-पाखण्डी वेश में ऐसे लोग भी सामने आने लगे हैं जो धार्मिक कार्यकलापों की बजाय न केवल अर्थार्जन में जुटे रहते हैं बल्कि अंधविश्वास, व्यभिचार और पाखण्ड को बढ़ावा देने में जुटे हैं। छद्म धर्मगुरु और संत लोगों की धार्मिक श्रद्धा एवं अंधभक्ति का फायदा उठाकर उन्हें ठगते हैं। ऐसे लोगों का गाहे-बगाहे सियासी जुड़ाव भी सामने आता रहता है। ऐसे ही लोग संत समाज को बदनाम करते हैं, जिससे लोगों की धार्मिक आस्था भी डगमगाने लगती है।

धर्मगुरुओं के धन के प्रति बढ़ते आकर्षण ने भी अनेक तरह की विसंगतियों एवं विकृतियों को जन्म दिया है। अब तक धर्म और धर्मगुरुओं के इर्द-गिर्द ठाट-बाट और राजा-महाराजाओं जैसी वैभवपूर्ण स्थितियां ही देखने को मिलती थीं, लेकिन अब ये तथाकथित धर्मगुरु स्वयं व्यापारी बनकर बड़ी-बड़ी कंपनियों का संचालन कर रहे हैं। एक प्रमुख महिला धर्मगुरु बहुत सारे धार्मिक कार्यों के अलावा अस्पताल, एक टीवी चैनल, इंजीनियरिंग कॉलेज और बिजनेस स्कूल चलाती है। हाल ही में दिल्ली में आयोजित हुए विश्व धार्मिक सांस्कृतिक सम्मेलन में देखा कि किस तरह से पानी से लेकर खाद्य पदार्थ तक बेचे गए। एक बड़ा पंथ चलाने वाले राम-रहीम ऑर्गेनिक उत्पाद खिलाकर देश को सेहतमंद बनाने की तमन्ना रखते हैं। ये एक ऐसी लंबी सूची है जिसमें वर्तमान के लगभग सभी चर्चित धर्मगुरु ऐसे ही व्यावसायिक कार्यों और लाभकारी इकाइयों से जुड़े हैं। व्यावसायिक लाभों के लिए राजनीतिक और व्यावसायिक नेटवर्क रखने के साथ-साथ बड़ी संख्या में धार्मिक अनुयायी रखना इन तथाकथित धर्मगुरुओं की परंपरा रही है।

राजनीति पर धर्म के अनुशासन की बात उचित है, लेकिन धर्मगुरुओं को प्रतिष्ठापित करने के बहाने राजनीति का खेल न खेला जाए, इस बात की जरूरत सर्वाधिक है। अपनी लोकप्रियता के बल पर कुछ धर्मगुरु भारतीय राजनीति के बदलते दौर में कुछ सीटें जीतकर सामने आए हैं। धर्मगुरु से राजनीतिज्ञ बन जाने की ये घटनाएं न केवल धर्मक्षेत्र के लिए बल्कि राजनीति के लिए भी घातक हैं। जहां धर्मगुरुओं के अनुयायी अधिक संख्या में हैं, उन क्षेत्रों में वे स्वयं जीतें न जीतें, वहां के परिणाम को प्रभावित कर ही सकते हैं। उनका यह असर किस दिशा में होगा? कौन सी बड़ी ताकत को लाभ मिलेगा? यानी राजनीति एवं राजनेताओं पर इन धर्मगुरुओं एवं बाबाओं का गहरा प्रभाव एवं वर्चस्व भी अनेक विसंगतियों का कारण बना है। हाथरस में सूरजपाल जाटव उर्फ साकार हरि 'बाबा' के तथाकथित सत्संग में 121 लोगों की मौत का कारण बना। ऐसे फर्जी एवं तथाकथित चमत्कारी बाबाओं के चक्कर लगाने वालों में महिलाएं एवं दलित बड़ी संख्या में हैं। भगदड़ एवं अन्य हादसों की स्थिति में यही लोग मारे जाते हैं। प्रश्न है कि ढोंगी एवं पाखण्डी बाबाओं के पास जाने वाले लोग अपनी तर्क-बुद्धि एवं विवेक से काम क्यों नहीं लेते? अंधविश्वासों के सहारे तरक्की की सीढ़ियां क्यों चढ़ना चाहते हैं? ये विडंबनापूर्ण स्थितियां हैं। जनता की कमजोरी के कारण ही कभी हमारे यहां धर्म की राजनीति में घुसपैठ होती रही है तो अब आर्थिक गतिविधियों से उनका गठबंधन हो रहा है। जब-जब ऐसी स्थितियां हुई हैं, तब-तब धर्म और धर्मगुरु अपने विशुद्ध स्थान से खिसके हैं। खिसकते-खिसकते वे ऐसी डांवाडोल स्थिति में पहुंच गए हैं, जहां धर्म को अफीम कहा जाने लगा है। (लेखक-ललित गर्ग/ ईएमएस)

किसान आन्दोलन की समाधान राहें बातचीत से ही खुलेगी

मोदी सरकार 3.0 के पहले बजट में वित्त मंत्री ने सरकार की जिन 9 प्राथमिक्ताओं का जिक्र किया उसमें विकसित भारत लिये रोजगार, महंगाई नियंत्रण, कृषि, महिला-युवा विकास के साथ-साथ मध्यम वर्ग के लिये पहली बार सकारात्मक सोच सामने आयी है। बावजूद इसके विपक्षी दल किसी न किसी बहाने उसका विरोध करते हुए संसद में हंगामा बरपा रहे हैं। सभी क्षेत्रों के लिये न्यायसंगत एवं विकास योजनाओं के बावजूद विरोध होना अतिश्योक्तिपूर्ण है। विपक्षी दल इस आरोप के सहारे बजट का विरोध कर रहे हैं कि उसमें अन्य राज्यों के साथ भेदभाव किया गया है। इस विरोध का आधार बिहार और आंध्र प्रदेश की विभिन्न विकास योजनाओं के लिए विशेष घोषणाएं के साथ न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की वैधानिक गारंटी और अन्य मांगों को लेकर किसी तरह की घोषणा न करने के मुद्दे हैं। विपक्षी दल किसान आन्दोलन को उग्र करने के प्रयास करेंगे। ऐसा इसलिये भी लग रहा है कि बुधवार को ही नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से नई दिल्ली में मुलाकात करने के बाद किसान नेताओं ने साफ भी कर दिया है कि दिल्ली मार्च का उनका कार्यक्रम जारी रहेगा। संसद सत्र जारी है, ऐसे में किसान आंदोलन को लेकर प्रतिपक्ष सरकार पर हमलावर होगा, एक बार फिर किसान आन्दोलन के उग्र से उग्रतर होने की संभावनाएं हैं, जिससे आम जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने किसान-आन्दोलन से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए पंजाब-हरियाणा से सटे शंभू बॉर्डर पर यथास्थिति बनाए रखने का औचित्यपूर्ण आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी अहम है कि एक 'तटस्थ मध्यस्थ' की आवश्यकता है जो सरकार और किसानों के बीच विश्वास कायम कर सके। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए स्वतंत्र विशेषज्ञों की एक कमेटी बनाने का प्रस्ताव भी दिया है। प्रश्न है कि कांग्रेस एवं अन्य विपक्षी दल न्यायालय के इस महत्वपूर्ण सुझाव को आकार देने की बजाय किसान-आन्दोलन को उग्र करने की मंशा रखते हुए अराजक माहौल ही क्यों बनाना चाहते है? क्यों अव्यवस्था फैलाने चाहते हैं? निश्चित ही शंभू बॉर्डर खोले जाने पर कानून-व्यवस्था को लेकर संकट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। यह बात सही है कि शंभू बॉर्डर खोले जाने से आंदोलनरत किसानों के दिल्ली कूच की राह खुल सकती है। आंदोलनरत किसान संगठन पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि जब भी सीमाएं खुलेंगी, किसान ट्रैक्टर ट्रोलियों के साथ दिल्ली की ओर बढ़ेंगे। शीर्ष अदालत हरियाणा सरकार की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें उसे एक सप्ताह के भीतर अंबाला के पास शंभू सीमा पर बैरिकेड्स हटाने के लिए कहा गया था जहां किसान 13 फरवरी से डेरा डाले हुए हैं।

केन्द्र सरकार एवं विपक्षी दलों को मिलकर इस विकट समस्या का समाधान निकालने के लिये कोई सार्थक प्रयास करने चाहिए। किसानों के भरोसे को जीतने की कोशिश होनी चाहिए। लेकिन नेशनल हाई-वे पर जेसीबी और बख्तरबंद ट्रैक्टर ट्रॉली की इजाजत तो इस समस्या का समाधान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने विशेषज्ञों की समिति के जरिए बातचीत का जो प्रस्ताव दिया है उस पर सरकार की प्रतिक्रिया आनी बाकी है। लेकिन दोनों पक्षों को ही आंदोलन खत्म करने के लिए बातचीत के माध्यम से समाधान का रास्ता निकालने की पहल करनी होगी। किसान आंदोलन के उग्र रूप को भी यह देश देख चुका है, भारी नुकसान भी हुआ है। किसानों की समस्याएं अपनी जगह हैं और इनकी आड़ में होने वाली राजनीति अपनी जगह। वैसे भी स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू करने, न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी और कर्ज माफी जैसे मुद्दों पर समिति के गठन का प्रस्ताव केन्द्र सरकार पहले ही दे चुकी है। यह बड़ा सच है कि बात करने से ही बात बनती है। बातचीत की हर संभावना का स्वागत किया जाना चाहिए। किसी भी आंदोलन का लंबे वक्त तक जारी रहना सचमुच चिंताजनक है। ऐसे आन्दोलन को उग्र करने की विपक्षी दलों की मानसिकता भी संदेहों एवं अविश्वासों से घिरी है। अच्छा हो कि विपक्षी दल एवं नेता प्रचार पाने के लिए विरोध की बेतुकी रस्म निभाने के बजाय बजट में कृषि क्षेत्र के लिये किये गये बड़े ऐलानों पर गौर करें। सरकार ने एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं। इनमें कृषि उत्पादकता को बढ़ाने और जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए मौसम में बदलाव को बरदाश्त कर सकने वाली फसलों की प्रजातियों को विकसित करने पर जोर दिया गया है। इसके लिए एग्रीकल्चर रिसर्च के बजट को भी बढ़ाया गया है।

विपक्षी पार्टियां लगातार किसानों एवं कृषि को लेकर सरकार को घेरने का प्रयास कर रही हैं। कोई न कोई बहाना चाहिए विरोध का, अब किसान-आन्दोलन के सहारे अपनी राजनीति चमकाने की जुगत में देश का कितना नुकसान होगा, कहा नहीं जा सकता। जबकि भाजपा सरकार द्वारा भारतीय अर्थ-व्यवस्था की वृद्धि और विकास में कृषि की भूमिका को ध्यान में रखते हुए, इस बजट में कृषि क्षेत्र पर अधिक ध्यान दिया गया है। कृषि में उत्पादकता, किसानों के हितों एवं कृषि की सुदृढ़ता को बढ़ाना बजट द्वारा निर्धारित शीर्ष प्राथमिकताओं में से एक है। उल्लेखनीय है कि बजट में जो नौ प्राथमिकताएं शामिल है, उनमें कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों के लिए करीब 1.52 लाख करोड़ रुपये के आवंटन से खेती-किसानी की दशा-दिशा सुधरने की आस बढ़ी है। विभिन्न फसलों की प्रस्तावित 109 किस्मों से भी उत्पादकता में बढ़ोतरी की उम्मीद है। ये किस्में जलवायु परिवर्तन के चलते बढ़ रही प्रतिकूल मौसमी परिघटनाओं के विरुद्ध कवच का काम करेंगी। दलहन-तिलहन को प्राथमिकता, डिजिटल क्राप सर्वे के अतिरिक्त किसान उत्पादक संघों यानी एफपीओ एवं भंडारण और आपूर्ति शृंखला पर ध्यान देने जैसे उपाय उपज को पहुंचने वाले नुकसान को घटाने एवं कीमतों में स्थायित्व सुनिश्चित करेंगे। ग्रामीण विकास के लिए 2.66 लाख करोड़ की बड़ी राशि आवंटित की गई है। भले ही सरकार ने सीधे तौर पर बजट में किसानों की आय बढ़ाने और एमएसपी पर खरीद सुनिश्चित न किए जाने से किसानों को निराशा हुई हो लेकिन बजट में तिलहन में आत्मनिर्भरता, सब्जी उत्पादन केन्द्र विकसित करने और खेती के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास की बात कही गई है। विशेषज्ञों के मुताबिक इस बजट से आने वाले समय में एग्रीकल्चर सेक्टर की विकास की रफ्तार बढ़ाने में मदद मिलेगी जो सीधे तौर पर किसानों की आय भी बढ़ायेगा एवं उन्नत कृषि को प्रोत्साहन भी देगा।

असल में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की वैधानिक गारंटी और अन्य मांगें राजनीतिक मुद्दे बन गये हैं, जिनके चलते हो रहा आन्दोलन न केवल किसानों के बल्कि आम जनता के लिये भी परेशानी का सबब है। जबकि सरकार ने धान का उत्पादन करने वाले किसानों के लिए एमएसपी को बढ़ा कर 2300 कर दिया है जो स्वागत योग्य कदम है। उम्मीद थी की सरकार एमएसपी पर खरीद को सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाएगी। लेकिन बजट में इस तरह का कोई प्रावधान न होने से काफी निराशा हुई है। दुनिया भर के विकसित देश अनिवार्य रूप से किसानों की उपज को एमएसपी पर खरीदते हैं। लेकिन भारत में किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य नहीं मिल पाता। विपक्षी दल किसानों के हित में आन्दोलन की बजाय बातचीत के रास्ते पर आगे बढ़े। स्तरीय विरोध हो, किसानों को गुमराह करने एवं उनका मनोबल कमजोर करने के लिये विपक्षी दल उजालों पर कालिख न पोते, इससे उन्हीं के हाथ काले होने की संभावनाएं है। (लेखक-ललित गर्ग/ ईएमएस)

अगर यह सुशासन है तो जंगल राज क्या है ?

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की ज़िम्मेदारी संभालने के जब डॉ.मोहन यादव ने यह कहना शुरू किया था कि राज्य में क़ानून व्यवस्था से कोई समझौता नहीं किया जाएगा उस समय प्रदेशवासियों में यह उम्मीद जगी थी कि प्रदेश को मिला नया नेतृत्व शायद राज्य से भय,आतंक व अराजकता के वातावरण को दुरुस्त कर सकेगा। परन्तु राज्य के हालात क़ानून व्यवस्था से लेकर भ्रष्टाचार तक अभी भी न केवल जस के तस बने हुये हैं बल्कि अपराधियों द्वारा अंजाम दी जाने वाली कुछ घटनाओं से तो ऐसा प्रतीत होने लगा है गोया सत्ता बदलने या मुख्यमंत्री की क़ानून व्यवस्था सम्बन्धी किसी चेतावनी का अपराधियों पर कोई असर ही नहीं। हद तो यह है कि प्रदेश में घटी अनेक बड़ी आपराधिक घटनाओं में सत्तारूढ़ भाजपा के लोगों के शामिल होने के भी प्रमाण मिलते रहे हैं। तभी विपक्ष को भी पूछना पड़ रहा है कि प्रदेश में होने वाली हर बड़ी आपराधिक घटनाओं के पीछे कहीं न कहीं बीजेपी से जुड़े लोग शामिल होते पाए गए हैं। तो क्या सरकार और पार्टी इस दिशा में कोई क़दम उठाने वाली है? विपक्ष यह भी पूछ रहा है कि मध्य प्रदेश सरकार को जंगलराज के टैग से मुक्ति कब मिलेगी ? और विशेषकर अनुसूचित जाति जनजाति पर होने वाले अत्याचार कब समाप्त होंगे ?

पिछले दिनों मध्य प्रदेश के रीवा ज़िले में इलाहबाद मार्ग पर स्थित मंगावा थाना क्षेत्र के अंतर्गत दबंगों द्वारा अपनी दबंगई का वह प्रदर्शन किया गया जो शायद आजतक उस बिहार व उत्तर प्रदेश जैसे उन राज्यों में भी नहीं हुआ जहाँ लालू यादव व अखिलेश यादव के राज को जंगल राज कहकर यही सत्ताधारी भाजपाई आज भी सम्बोधित किया करते हैं। रीवा ज़िले के हिनौता क्षेत्र में हुई इस घटना में गुंडों ने डंपर से बजरी फेंककर दो महिलाओं को ज़िंदा दफ़नाने की कोशिश की। इस घटना में ममता पांडे और आशा पांडे नाम की दो महिलाएं बजरी के ढेर में कमर और गर्दन तक दब गई थीं। जिन्हें स्थानीय लोगों ने फावड़े की सहायता से बजरी के ढेर में से बाहर निकाल कर उनकी जान बचाई। इन महिलाओं को बेहोशी की हालत में इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। यदि स्थानीय लोग मानवता का प्रदर्शन करते हुये उन महिलाओं को समय रहते बजरी के ढेर से बाहर न निकालते तो दोनों महिलाएं ज़िंदा ही दफ़्न हो जातीं। बताया जा रहा है कि इस गांव में एक सड़क निर्माण योजना को लेकर महिलाएं विरोध प्रदर्शन कर रही थीं। उन महिलाओं का दावा है कि चूँकि यह ज़मीन उन्हें सरकार द्वारा पट्टे पर दी गई थी इसीलिये वे उस ज़मीन पर सड़क निर्माण का विरोध कर रही थीं। और जब उन्होंने सड़क निर्माण रोकने की कोशिश की तो उन पर जानलेवा हमला किया गया। पीड़ित महिलाओं ने गौकरण प्रसाद पांडे, महेंद्र प्रसाद पांडे सहित अन्य कई व्यक्तियों पर हमला करने और डंपर चालक पर उन्हें ज़िंदा दफ़नाने की कोशिश करने का आरोप लगाया है।

मोहन यादव सरकार से पहले शिवराज चौहान सरकार में भी इस राज्य में मानवता को शर्मसार करने वाली दबंगई की कई शर्मनाक घटनायें हो चुकी हैं। गत वर्ष जुलाई माह में मध्य प्रदेश के छतरपुर ज़िला मुख्यालय से लगभग 35 किलोमीटर दूर बिकौरा गांव में पंचायत के लिए नाली का निर्माण कार्य चल रहा था।उस समय रामकृपाल पटेल नामक व्यक्ति पास के एक हैंडपंप पर नहा रहा था। बताया जाता है कि उसी समय दलित समुदाय के एक व्यक्ति दशरथ अहिरवार ने हंसी मज़ाक़ के माहौल में ग्रीस लगे हाथ से आरोपी रामकृपाल पटेल को छू लिया। तभी ग़ुस्साया पटेल नहाने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे मग में पास में पड़ा मानव मल भर लाया और इसे दशरथ अहिरवार के सिर और चेहरे सहित पूरे शरीर पर भी लगा दिया। पीड़ित दलित दशरथ अहिरवार ने यह भी आरोप लगाया कि पटेल ने इस दौरान उसे जाति के आधार पर अपमानित भी किया। और जब उसने मामले की सूचना पंचायत को दी और बैठक बुलाई। तो पंचायत ने उल्टे उसी पर 600 रुपये का जुर्माना भी लगा दिया।

यह वही मध्य प्रदेश राज्य है जहाँ गत वर्ष जुलाई में सीधी से भाजपा विधायक केदारनाथ शुक्ला के प्रतिनिधि के रूप में कार्यरत प्रवेश शुक्ला नामक एक युवक ने एक आदिवासी युवक के मुंह व चेहरे पर पेशाब करते अपनी वीडियो बनवाई थी। बाद में आरोपी प्रवेश शुक्ला के विरुद्ध बहारी थाने में भारतीय दंड संहिता की धाराओं 294 (अश्लील हरकतें), 504 (शांति भंग करने के लिए जानबूझकर अपमान) और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया था। साथ ही आरोपी के विरुद्ध एनएसए की कार्रवाई भी शुरू की गई थी। मानवता को आहात करने वाली इस घटना ने पूरे मध्य प्रदेश को शर्मसार कर दिया था। इस घटना की वीडिओ भी वायरल हुई थी। इस घटना का ज़िक्र विदेशी मीडिया ने भी किया था। वैसे भी मध्य प्रदेश पूरे देश में दलितों के साथ अपराध के मामलों में तीसरे स्थान पर है। विपक्ष यह भी पूछ रहा है कि मध्य प्रदेश सरकार को जंगलराज के टैग से मुक्ति कब मिलेगी ?

एक दो दशक पहले के ख़ासकर उत्तर प्रदेश व बिहार में अन्य दलों के शासन को आज भी गुंडा राज कहकर याद करने वाली भाजपा के शासन में आख़िर कौन सा अपराध नहीं हो रहा है ? पुलिस कस्टडी में लोगों की संदिग्ध अवस्था में हत्यायें हो जाना क्या अराजकता की निशानी नहीं ? गैंग रेप, अपहरण दलितों व अल्पसंख्यकों पर ज़ुल्म क्या यह बेहतर क़ानून व्यवस्था के लक्षण हैं ? जेल में गैंगवार और हत्यायें बेहतर क़ानून व्यवस्था की परिचायक तो हरगिज़ नहीं? दरअसल भाजपा नेताओं व सरकार की प्राथमिकतायें कुछ और ही हैं। छोटे मोटे अपराधों को लेकर समुदाय विशेष के लोगों के घरों व व्यवसायिक ठिकानों पर बुलडोज़र चलाकर दूसरे समुदाय के लोगों की वाहवाही लूटना यानी एक की बर्बादी दिखाकर दूसरों को ख़ुश करना यही इनकी लोकप्रियता का शार्ट कट है। अन्यथा डंपर से बजरी फ़ेंक कर दो महिलाओं को ज़िंदा दफ़्न करने से बड़ा अपराध और क्या हो सकता है ? देश के तमाम मीडिया ने इस घटना को तालिबानी कृत्य का नाम दिया। यहाँ आख़िर बुलडोज़र क्यों नहीं चला ? यदि इस तरह के दुस्साहसिक गुंडा राज के दौर को भी सुशासन बताने की कोशिश की जाये फिर आख़िर जंगल राज किसे कहा जाये ? (लेखिका - निर्मल रानी/ईएमएस)

शब्द पहेली - 8080

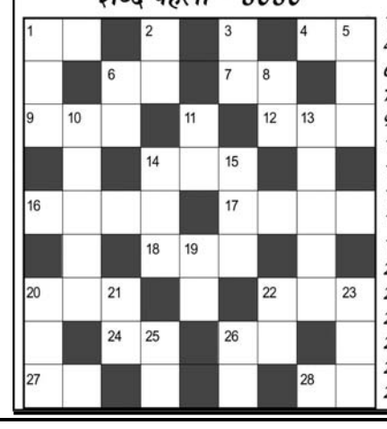

बाएँ से दाएँ

1. उचित, गलत का विलोम-2
4. अधिकार-2
6. परछाई-2
7. सम्मान, प्रसिद्धि-2
9. उल्टी, कै, वमन-3
12. रंग (अंग्रेजी-3)
14. चंचल, फुर्तीला-3
16. भयभीत होना-4
17. फुर्तीलापन-4
18. बसंत काल-3
20. भ्रम, वहम-3
22. आश्रय, शरण-3
24. राजनीतिक पार्टी-2
26. शारीरिक ऊंचाई-2
27. गन्ना-2
28. शाखा, टहनी-2

ऊपर से नीचे

1. नमस्ते, आदाब-3
2. देह, बदन, तन-2
3. शराब, मदिरा-2
5. डोली उठानेवाले-3
6. पत्नी की छोटी बहन -2
8. वहम, संदेह-2
10. जरुरतमंद-5
11. नाग, सर्प-2
13. आनंदित होना -5
14. भारत से निकलने वाली नदी जो पाकिस्तान में खत्म होती है-3
15. ढीला, सुस्त-3
19. नुकसान, घाटा-2
20. सद्कार्य-3
21. नशा, सरुर, खुमार-2
22. ओहदा -2
23. भवन, कोठी-3
25. क्षण, पल-2
26. कलिका, फूल खिलने से पहले की स्थिति-2

शब्द पहेली -8079 का हल

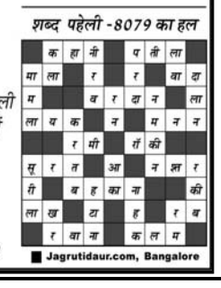

Jagrutidaur.com, Bangalore

खेल - समाचार

सूर्यकुमार और गंभीर करेंगे अपनी नई पारी की शुरुआत

पल्लेकेले (ईएमएस)। भारत और श्रीलंका के बीच शनिवार से यहां शुरु हो रही तीन मैचों की टी20 सीरीज से नये कोच गौतम गंभीर और कप्तान सूर्यकुमार यादव एकसाथ मिलकर अपने काम-काज की शुरुआत करेंगे। इस दौरे में इन दोनो की पहली परीक्ष होगी क्योंकि कई युवा खिलाड़ियों के साथ उतर रही है। । भारत और श्रीलंका के बीच 27 जुलाई से टी20 सीरीज का आगाज होने जा रहा है। टीम चयन में गंभीर को पूरी आजादी मिली और ऐसे में टीम को जीत दिलाना उ

सूर्यकुमार की कप्तानी में श्रीलंका के खिलाफ जीत से शुरुआत करने उतरेगी भारतीय टीम

पालेकल (ईएमएस)। भारतीय क्रिकेट टीम शनिवार को नये कोच गौतम गंभीर और कप्तान सूर्यकुमार यादव के नेतृत्व में मेजबान श्रीलंका के खिलाफ पहले टी20 में जीत के इरादे से उतरेगी। भारतीय टीम इस दौरे में श्रीलंका से तीन मैच खेलेगी और गंभीर व सूर्या की जोड़ी का लक्ष्य इसमें टीम को जीत दिलाना रहेगा।

गंभीर को राहुल द्रविड़ की जगह कोच बनाया गया है। गंभीर को अब उनके काम को आगे बढ़ाना होगा। गंभीर को इस दौरे में उनकी मांग के अनुसार टीम दी गयी है। ऐसे में उनकी पहली परीक्षा ये दौरा होगा। इस दौर में सूर्यकुमार को कप्तान बनाया गया है जबकि हार्दिक पंडया इस पद के स्वाभाविक दावेदार माने जा रहे थे। इसके अलावा कई युवा खिलाड़ियों को भी अवसर मिला है।

भारतीय टीम में यह बदलाव पिछले महीने विश्व कप जीतने तथा रोहित, विराट कोहली और रविंद्र जडेजा के टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद आया है। इस सीरीज में उपकप्तानी संभाल रहे शुभमन गिल इसे अपनी जगह पक्की करने के अवसर के रूप में देखेंगे। इसके अलावा यशस्वी जायसवाल, रिंकू सिंह और यहां तक कि रियान पराग जैसे अन्य खिलाड़ी भी यही चाहेंगे। अक्षर पटेल टीम में जडेजा की जगह लेने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। उनके अलावा भारत के पास हार्दिक, शिवम दुबे और वाशिंगटन सुंदर जैसे बेहतरीन ऑलराउंडर हैं।

इस दौरे में अनुभवी तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को आराम दिया गया है और ऐसे में गेंदबाजी की कमान अर्शदीप सिंह और मोहम्मद सिराज पर रहेगी। बल्लेबाजी की जिम्मेदारी शुभमन , सूर्यकुमार जैसे बल्लेबाजों पर रहेगी। वहीं दूसरी ओर मेजबान श्रीलंकाई टीम की राह भी आसान नहीं है। उसके दो अनुभवी गेंदबाज दुष्मंथा चमीरा चोटिल होने के कारण सीरीज से बाहर हो गये हैं। अब उनकी जगह असिथा फर्नांडो और दिलशान मदुशंका को टीम में लिया गया है।

श्रीलंकाई टीम इस सीरीज में नये कतान चरिथ असलांका और अंतरिम कोच सनत जयसूर्या के मार्गदर्शन में उतरेगी। मेजबान टीम घरेलू हालातों का लाभ उठाकर बेहतर प्रदर्शन करना चाहेगी। उसके पास दासुन शनाका, कुसल परेरा, कुसल मेंडिस और दिनेश चांदीमल जैसे अनुभवी खिलाड़ी हैं। गेंदबाजी की जिम्मेदारी वानिंदु हसरंगा, मथीशा पथिराना जैसे खिलाड़ियों के पास रहेगी।

सोना 500 रुपए बढ़ कर 67,850, चांदी 81,400 रुपए

नई दिल्ली (ईएमएस)। सोने-चांदी के वायदा भाव में गुरुवार को बड़ी गिरावट के बाद शुक्रवार को सुधार देखने को मिल रहा है। शुक्रवार को दोनों के वायदा भाव तेजी के साथ खुले। सोने के वायदा भाव 67,850 रुपये के करीब, जबकि चांदी के वायदा भाव 81,400 रुपये के करीब कारोबार कर रहे थे। अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी सोने व चांदी के वायदा भाव में तेजी देखी जा रही है। सोने के वायदा भाव की शुरुआत आज तेजी के साथ हुई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर सोने का बेंचमार्क अगस्त कॉन्ट्रेक्ट 528 रुपये की तेजी के साथ 67,990 रुपये के भाव पर खुला। इस समय यह 387 रुपये की तेजी के साथ 67,849 रुपये के भाव पर कारोबार कर रहा था। चांदी के वायदा भाव की शुरुआत आज तेज रही। एमसीएक्स पर चांदी का बेंचमार्क सितंबर कॉन्ट्रेक्ट 331 रुपये की तेजी के साथ 81,662 रुपये पर खुला। इस समय यह 69 रुपये की तेजी के साथ 81,400 रुपये के भाव पर कारोबार कर रहा था। वै?श्विक बाजार में सोने-चांदी के वायदा भाव की शुरुआत तेजी के साथ हुई। कॉमेक्स पर सोना 2,363.80 डॉलर प्रति औंस के भाव पर खुला। पिछला बंद भाव 2,353.50 डॉलर प्रति औंस था। ?फिलहाल यह 18.80 डॉलर की तेजी के साथ 2,372.30 डॉलर प्रति औंस के भाव पर कारोबार कर रहा था। कॉमेक्स पर चांदी के वायदा भाव 27.99 डॉलर के भाव पर खुले, पिछला बंद भाव 27.97 था। ?फिलहाल यह 0.04 डॉलर की तेजी के साथ 28.01 डॉलर प्रति औंस के भाव पर कारोबार कर रहा था।

शेयर बाजार तेजी के साथ बंद

मुम्बई (ईएमएस)। घरेलू शेयर बाजार शुक्रवार को तेजी के साथ बंद हुआ। सप्ताह के अंतिम कारोबारी दिन बाजार में ये उछाल दुनिया भर से मिले अच्छे संकेतों के साथ ही दिग्गज कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में आये उछाल से आया है। दिन भर के कारोबार के बाद 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 1,292.92 अंक करीब 1.62 फीसदी ऊपर आकर 81,332.72 पर बंद हुआ। वहीं 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 428.75 अंक तकरीबन 1.76 फीसदी बढ़कर 24,834.85 के शीर्ष स्तर पर बंद हुआ।

आज के कारोबार में सेंसेक्स के 29 शेयर लाभ पर बंद हुए। भारती एयरटेल, अदाणी पोर्ट्स, टाटा स्टील, जेएसडब्लयू स्टील और इंफोसिस सेंसेक्स के शेयर सबसे अधिक लाभ में रहे। भारती एयरटेल 4.51 फीसदी से ज्यादा की बढ़त के साथ सबसे अधिक लाभ में रही। इसके अलावा सन फार्मा, एचसीएल टेक, एमएंडएम, आईटीसी, टाटा मोटर्स, टाइटन, कोटक बैंक, अल्ट्राटेक सीमेंट, बजाज फाइनैंस, एसबीआई, इंडसइंड, एशियन पेंट्स, टीसीएस, पावर ग्रिड, एलएंडटी, मारुति, रिलायंस, एनटीपीसी, आईसीआईसीआई बैंक, बजाज फिनसर्व, टेक महिंद्रा, एक्सिस बैंक, एचयूएल और एचडीएसफसी बैंक के शेयर भी लाभ में रहे।

वहीं, दूसरी तरफ सेंसेक्स के 30 शेयरों में से केवल एक शेयर ही नुकसान पर बंद हुआ। ये शेयर नेस्ले इंडिया का था। इसमें 0.07 फीसदी की हल्की गिरावट रही।

वहीं दुनिया भर के बाजारों की बात करें तो एशियाई बाजारों में, सियोल, शंघाई और हांगकांग ऊपर आये जबकि टोक्यो में गिरावट रही। यूरोपीय बाजार भी ऊपर आया है। गत दिवस अमेरिकी बाजार में गिरावट रही।

बजट के बाद कई राज्यों में पेट्रोल और डीजल की कीमत घटी

नई दिल्ली (ईएमएस)। केंद्र सरकार के तीसरे कार्यकाल के बजट पेश होने के बाद कई चीजों के दाम में बदलाव देखने को मिला है। वहीं बजट के बाद कई राज्यों में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बदलाव देखने को मिल रहा है। शुक्रवार को भी कई राज्यों में पेट्रोल-डीजल के दाम कम हुए हैं। हालांकि कीमतों में बदलाव आंशिक है। जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार में पेट्रोल-डीजल के दाम में कमी आई है तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में आज पेट्रोल और डीजल के भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ है। जबकि महाराष्ट्र में कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 94.72 रुपये और डीजल की कीमत 87.62 रुपए प्रति लीटर, मुंबई में पेट्रोल की कीमत 103.44 रुपये और डीजल की कीमत 89.97 रुपए प्रति लीटर, कोलकाता में पेट्रोल की कीमत 104.95 रुपये और डीजल की कीमत 91.76 रुपए प्रति लीटर, चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 100.75 रुपये और डीजल की कीमत 92.34 रुपए प्रति लीटर है। बिहार में पेट्रोल 3 पैसे घटकर 107.09 रुपए प्रति लीटर और डीजल 3 पैसे घटकर 93.81 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। यूपी में पेट्रोल 10 पैसे घटकर 94.39 रुपए प्रति लीटर और डीजल 11 पैसे घटकर 87.44 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। वहीं महाराष्ट्र में पेट्रोल-डीजल महंगा हो गया है। यहां पेट्रोल 1 रुपए 22 पैसे बढ़कर 105.09 रुपये प्रति लीटर और डीजल 1 रुपए 17 पैसे घटकर 91.59 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है।

साल 2022-23 में 10 में से 7 लोग इंट्राडे ट्रेडिंग में नुकसान में रहे

- इंट्राडे ट्रेडिंग शेयर खरीदने-बेचने वालों की संख्या में भी बहुत ज्यादा बढ़ोतरी देखी गई

नई दिल्ली (ईएमएस)। सेबी के एक अध्ययन में बताया गया ?कि साल 2022-23 में 10 में से 7 लोगों ने इक्विटी कैश सेगमेंट में इंट्राडे ट्रेडिंग से नुकसान उठाया। वहीं इसी दौरान इंट्राडे ट्रेडिंग शेयर खरीदने-बेचने वाले लोगों की संख्या में भी बहुत ज्यादा बढ़ोतरी देखी गई है। साल 2018-19 के मुकाबले ये संख्या तीन गुनी से ज़्यादा हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक ?जिन लोगों को शेयर बाजार में नुकसान हो रहा है वे ज़्यादा कारोबार कर रहे हैं। इसके अलावा 30 साल से कम उम्र के युवाओं की संख्या भी शेयर बाज़ार में तेज़ी से बढ़ रही है। शेयर बाज़ार का नियमन करने वाली संस्था सेबी ने यह रिपोर्ट हाल ही में जारी की। इसमें साल 2018-19, 2021-22 और 2022-23 के आंकड़ों का अध्ययन किया गया है। इसमें कोरोना काल भी शामिल है। इस रिपोर्ट के लिए देश के टॉप 10 ब्रोकरेज हाउस के ग्राहकों के आंकड़ों का उपयोग किया गया है। इन 10 ब्रोकरेज हाउस के पास देश के कुल शेयर बाज़ार ग्राहकों का लगभग 86 फीसदी हिस्सा है।

इस रिपोर्ट को कई जानकारों ने देखा और सुझाव दिए हैं। रिपोर्ट में बताया गया है ?कि हर तीन में से एक व्यक्ति शेयर बाज़ार में इंट्राडे ट्रेडिंग करता है। इसके अलावा, इस तरह के ट्रेड में 30 साल से कम उम्र के युवाओं की संख्या तेज़ी से बढ़ रही है। साल 2018-19 में ये संख्या 18 फीसदी थी, जो अब बढ़कर 48 फीसदी हो गई है। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा कारोबार करता है तो उसके नुकसान होने की संभावना और भी बढ़ जाती है। ऐसे लोगों में से 80 फीसदी लोग घाटे में रहे हैं। साल 2022-23 में नुकसान उठाने वाले लोगों ने अपने नुकसान का 57 फीसदी हिस्सा कारोबार के खर्चों में लगाया, जबकि मुनाफा कमाने वालों ने अपने मुनाफे का सिर्फ 19 फीसदी हिस्सा खर्च किया। इसके अलावा कम उम्र के लोगों में नुकसान उठाने वालों की संख्या ज़्यादा है। साल 2022-23 में 76 फीसदी युवा ट्रेडर घाटे में रहे। सेबी का मानना है कि इस रिपोर्ट से लोगों को इंट्राडे ट्रेडिंग में होने वाले जोखिम के बारे में पता चलेगा। शेयर बाज़ार में फ्यूचर और ऑप्शन वाले हिस्से में ज़्यादातर लोगों को नुकसान हुआ है।

एक रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2022 में 89 फीसदी लोगों ने इस हिस्से में पैसा गंवाया। हर व्यक्ति ने औसतन 1.1 लाख रुपये का नुकसान उठाया। इसके अलावा कोरोना काल के दौरान एफएंडओ में कारोबार करने वाले लोगों की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ी। साल 2019 में ऐसे लोगों की संख्या 7 लाख थी, जो साल 2021 में बढ़कर 45 लाख हो गई। यह संख्या 500 फीसदी से ज़्यादा बढ़ी है।

शेयरों में लगाएं पैसा या सोने में करें निवेश, जानिए निवेश सलाहकारों से

नई दिल्ली (ईएमएस)। केंद्र सरकार के आम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोने की कस्टम डयूटी घटा कर 6 फीसदी कर दी है, इससे देश में सोने के भाव में ?गिरावट आ गई है। वैसे निवेश के लिहाज से अगर हम पिछले पांच वर्षों को देखें तो सोने ने शेयरों से ज्यादा रिटर्न दिया है। इस अवधि में निफ्टी 50 का रिटर्न 13.95 फीसदी तो सोने का 16.21 फीसदी रहा है। हालांकि, 20 वर्ष और 10 वर्ष में शेयर बाजार का रिटर्न सोने से ज्यादा रहा है। ऐसे मे अब सवाल यह है कि एक आम निवेशक को सोने में निवेश ज्यादा करना चाहिए या फिर शेयर बाजार में? निवेश सलाहकारों का कहना है कि साल 2024 की दूसरी छमाही में स्टॉक्स और गोल्ड दोनों में स्थिर वृद्धि की उम्मीद है। मिड टर्म में निफ्टी 50 25,600-26,000 तक पहुंच सकता है, जबकि साल के आ?खिर तक सोने का भाव 81,500 तक जा सकता है।

ऐसे में निवेशकों को संतुलित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और अपने जोखिम प्रोफाइल के आधार पर दोनों में धन आवंटित करना चाहिए। एक रिपोर्ट के मुताबिक मेहता इक्विटीज लिमिटेड के एक वीपी कमोडिटीज का सुझाव है कि निवेशकों को अपने पोर्टफोलियो की समीक्षा करनी चाहिए और शेयरों से कुछ लाभ निकालकर सोने में निवेश करना चाहिए। उनका कहना है कि निवेशक आमतौर पर अपने एसेट का 10-15 फीसदी कीमती धातुओं में निवेश करते हैं, लेकिन वर्तमान में इस आवंटन को बढ़ाकर 30-35 फीसदी कर लेना चाहिए। उनका कहना है कि यूएस दर में कटौती के बाद सोने में और भी वृद्धि हो सकती है। रेलिगेयर ब्रोकिंग लिमिटेड के एक ??निवेश सलाहकार कहते है कि निफ्टी मिड टर्म में 25,600-26,000 के स्तर को छू सकता है। सोना भी इस साल के अंत तक 81,500 रुपये प्रति 10 ग्राम तक जा सकता है। वे निवेशकों को सलाह देते हैं कि वे संतुलित दृष्टिकोण अपनाएं और अपने जोखिम प्रोफाइल के आधार पर धन आवंटित करें। वर्तमान में स्टॉक्स और गोल्ड दोनों ही रिकॉर्ड उच्च स्तर पर हैं। ये दोनों ही विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं।

मॉस्को में कार बम विस्फोट करने वाला संदिग्ध तुर्की में गिरफ्तार

मॉस्को,(ईएमएस)। मॉस्को कार बम विस्फोट मामले में संदिग्ध येवगेनी सेरेब्रीकोव को तुर्की में गिरफ्तार किया गया और उसे रूस भेज दिया गया है। यह जानकारी रूसी संघीय सुरक्षा सेवा (एफएसबी) के जनसंपर्क विभाग ने शुक्रवार को मीडिया को दी।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बुधवार सुबह उत्तरी मॉस्को के सिन्याविंस्काया स्ट्रीट पर एक घर के आंगन में कार में विस्फोट हो गया था जिसमें दो लोग घायल हो गए थे। रूसी मंत्रालय के मुताबिक कार में रखी एक अज्ञात वस्तु में विस्फोट हुआ था। मॉस्को की ज़मोस्कोर्वोत्स्की कोर्ट ने स्पुतनिक से कहा कि उसने सेरेब्रीकोव को उसकी अनुपस्थिति में गिरफ्तार किया था।

एफएसबी ने जारी बयान में कहा कि रूसी संघीय सुरक्षा सेवा ने रूसी आंतरिक मंत्रालय के साथ और तुर्की के विशेष बलों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों की सहायता से, संदिग्ध को तुर्की के शहर बोडरम से हिरासत में लिया गया । बताया जा रहा है रूसी नागरिक येवगेनी सेरेब्रीकोव, जिनका जन्म 1995 में हुआ था, जो कि अंतरराष्ट्रीय वांछित सूची में हैं। 24 जुलाई को उत्तरी मास्को में एक कार बम विस्फोट में शामिल था। बयान में कहा गया कि एफएसबी अधिकारियों ने संदिग्ध को हत्या के प्रयास और विस्फोटक या विस्फोटक उपकरणों के अवैध अधिग्रहण, हस्तांतरण, भंडारण, परिवहन करने के लिए जांचकर्ताओं को सौंप दिया है।

29 जुलाई का महत्वपूर्ण दिन.....जब तय होगी यूपी की राजनीतिक दिशा

लखनऊ (ईएमएस)। लोकसभा चुनाव के परिणामों के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में जबर्दस्त हलचल मची हुई है। बीजेपी में अंदरूनी गुटबाजी ने इनदिनों सुर्खियाँ बटोरी हैं और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर की है। बीजेपी के सहयोगी दल भी अब मुखर हो चुके हैं, अपनी ही सरकार पर सवाल उठाने लगे हैं। इस बीच, सपा प्रमुख और पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने लखनऊ को छोड़कर दिल्ली का रुख किया है। इस बदलती स्थिति ने 29 जुलाई को यूपी की राजनीति में महत्वपूर्ण मोड़ दे दिया है।

29 जुलाई को यूपी विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होगा और इसी दिन राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। अखिलेश ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है, जिससे विधानसभा में नए नेता प्रतिपक्ष का चुनाव भी इसी दिन होना है। सीएम योगी के लिए यह स्थिति चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि उन्हें पार्टी के भीतर चल रही गुटबाजी को सुलझाते हुए सहयोगी दलों का विश्वास भी प्राप्त करना होगा। सपा ने लोकसभा चुनाव में 80 में से 37 सीटें जीतकर अपनी ताकत का एहसास कराया है, जिससे उनके आत्मविश्वास में इजाफा हुआ है। इस विजय के बाद सपा विधानसभा में भी आक्रामक रुख अपनाने की योजना बना रही है। कांग्रेस का समर्थन भी उनकी स्थिति को मजबूत करता है। विपक्षी दलों के मुद्दों का सामना करना बीजेपी के लिए कठिन हो सकता है, खासकर जब मुद्दे बिजली कटौती, कांवड़ यात्रा के मार्ग पर नेम प्लेट विवाद और ओबीसी आरक्षण जैसे प्रमुख विषयों पर हो। बीजेपी और उसके सहयोगी दल भी अभी कशमकश में हैं।

उधर, राज्यपाल आनंदीबेन का कार्यकाल 29 जुलाई को समाप्त हो रहा है। इसी दिन विधानसभा सत्र की शुरुआत भी होगी, और नए राज्यपाल की नियुक्ति या कार्यकाल का विस्तार इसी दिन से पहले पूरा करना होगा। यूपी के इतिहास में किसी भी राज्यपाल को लगातार दो कार्यकाल नहीं मिले हैं, इसलिए यह देखना दिलचस्प होगा कि आनंदीबेन पटेल को केंद्र की मोदी सरकार विस्तार देती है या नया राज्यपाल नियुक्त करती है। अखिलेश यादव ने कन्नौज लोकसभा सीट से जीतने के बाद विधायकी पद से इस्तीफा दे दिया है, जिससे विधानसभा में नए नेता प्रतिपक्ष का चुनाव होना है। शिवपाल सिंह यादव, इंद्रजीत सरोज और रामअचल राजभर जैसे नाम इस पद के लिए सामने आ रहे हैं। 29 जुलाई का दिन उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होगा, जो प्रदेश की राजनीतिक दिशा और संभावनाओं को आकार देगा।

अल्जीरिया में तीन उम्मीदवार योग्य घोषित

अल्जीयर्स,(ईएमएस)। अल्जीरिया के नेशनल इंडिपेंडेंट अथॉरिटी फॉर इलेक्शन (एएनआईई) ने देश में सितंबर को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए तीन लोगों की उम्मीदवारी को मंजूरी दे दी है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एएनआईई के प्रमुख मोहम्मद चोर्फी ने सितंबर में होने वाले चुनावों के लिए उम्मीदवारों की जानकारी देने के लिए एक प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि एएनआईई ने राष्ट्रपति अब्देलमदजीद तेब्बौने, सोशलिस्ट फोर्सेज फ्रंट के महासचिव यूसेफ औचिचे और मूवमेंट ऑफ सोसाइटी फॉर पीस के प्रमुख अब्देलअली हसनी चेरीफ की उम्मीदवारी को मंजूरी दे दी गई है और उन्हें योग्य माना है क्योंकि वे निर्धारित सभी जरुरी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। अल्जीरिया के चुनावी कानून के मुताबिक चुनाव लड़ने के इच्छुक किसी भी उम्मीदवार को नगरपालिका, प्रांतीय या संसदीय परिषदों के चुने गए सदस्यों से 600 लोगों के हस्ताक्षर लेने होते हैं या कम से कम 29 प्रांतों में पात्र मतदाताओं में से कम से कम पचार हजार हस्ताक्षर लेने होते हैं, जिसमें प्रत्येक प्रांत से कम से कम बारह सौ हस्ताक्षर शामिल हैं। राष्ट्रपति तेब्बौने ने 21 मार्च को तकनीकी कारणों का हवाला देते हुए सात सितंबर को मध्यावधि राष्ट्रपति चुनाव कराने का फैसला लिया था। उन्होंने 11 जुलाई को अपने दूसरे कार्यकाल के लिए चुनाव लड़ने का भी ऐलान किया था।

श्रीलंका में 21 सितंबर को होगा राष्ट्रपति चुनाव

कोलंबो (ईएमएस)।श्रीलंका के चुनाव आयोग ने घोषणा किया कि देश में राष्ट्रपति चुनाव 21 सितंबर को होगा। चुनाव आयोग ने राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामांकन की तारीख 15 अगस्त घोषित की है।

चुनाव आयोग ने कहा कि देश के संविधान के मुताबिक राष्ट्रपति का कार्यकाल 17 नवंबर, 2024 को समाप्त हो रहा है। इतना ही नहीं राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान मौजूदा राष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति से करीब एक महीने और ज्यादा से ज्यादा दो महीने के बीच में ही किया जा सकता है। नवंबर 2019 में राष्ट्रपति चुनाव जीतने वाले गोटबाया राजपक्षे ने दक्षिण एशियाई देश में गंभीर आर्थिक संकट के बीच जुलाई 2022 में अपने पद से इस्तीफा दे दिया। राजपक्षे के इस्तीफे के बाद संसद में हुए चुनाव में रानिल विक्रमसिंघे को राष्ट्रपति चुना गया।

उत्तरी जापान में बाढ़ व भूस्खलन से सैकड़ों लोग बेघर, शरण लेने को मजबूर

टोक्यो,(ईएमएस)। देश ही नहीं इस बार बारिश ने कई दशों में तबाही मचा रखी है। उत्तरी जापान में भी भारी बारिश के बाद आई बाढ़ और भूस्खलन से आवागमन बाधित हो गया है और सैकड़ों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने को मजबूर हैं। जापान मौसम विभाग ने यामागाटा और अकिता प्रांत के कई शहरों के लिए चेतावनी जारी की है। इन शहरों में अब तक गर्म हवाएं चलने के कारण उमस से लोग परेशान थे। जापानी पीएम फूमियो किशिदा ने प्रभावित इलाकों के लोगों से मौसम संबंधी जानकारियों पर लगातार नजर बनाए रखने और सुरक्षा को प्राथमिकता देने की अपील की। अकिता प्रांत के युजावा शहर में एक व्यक्ति सड़क निर्माण स्थल पर भूस्खलन की चपेट में आने के बाद लापता बताया जा रहा है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक युजावा में बचाव कर्मियों ने नाव की मदद से बाढ़ग्रस्त क्षेत्र से 11 प्रभावित लोगों को सुरक्षित निकाला है। यामागाटा प्रांत में सबसे त्यादा प्रभावित युजा और सकाटा कस्बों में एक घंटे में चार इंच से ज्यादा बारिश हुई। क्षेत्र के हजारों लोगों को ऊंचे और सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने की सलाह दी गई। हालांकि, शरण लेने वाले लोगों की संख्या के बारे में तत्काल जानकारी नहीं मिल पाई है।

पूर्वी जापान यामागाटा शिंकानसेन बुलेट ट्रेन सेवाएं आंशिक रूप से निलंबित कर दी गईं हैं। यहां भारी बारिश होने का पूर्वानुमान जताया और लोगों से सतर्क रहने का आग्रह किया।

नाटो देशों की तरह भारत को टेक्नोलॉजी और हथियार मुहैया कराएगा अमेरिका

वॉशिंगटन(ईएमएस)। बीते रोज अमेरिकी सीनेट में लाए गए विधेयक में कहा गया है कि भारत की सुरक्षा के लिए अमेरिका को तत्पर रहने की जरुरत है। पाकिस्तान से आ रहा आतंकवाद और चीन से जुड़े सीमा विवाद जैसे मुददों पर भारत का सहयोग करना चाहिए। साथ ही प्रस्तावित विधेयक में ये भी कहा गया है कि अमेरिकी सरकार को भारत के साथ ठीक वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा कि वह अपने शीर्ष सहयोगियों के साथ करता है। जिस तरह अमेरिका नाटो के सहयोगियों के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और उनकी संप्रभुता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध रहते हैं ठीक वैसे ही हमें भारत के लिए भी तैयार रहना चाहिए।

विधेयक को प्रस्तुत करने के बाद रुबियो ने कहा,कम्युनिस्ट चीन लगातार अपनी विस्तारवादी नीति से इंडो पैसेफिक में अपनी सीमाओं का विस्तार करने की कोशिश कर रहा है। इस क्षेत्र में चीन की इन हरकतों को सुधारने के लिए हमें भारत के साथ-साथ अपने सभी सहयोगियों की हरसंभव मदद करने की जरूरत है।

रुबियो द्वारा लाया गया यह बिल भारत और अमेरिका के रिश्तों को आगे बढ़ाने में भूमिका निभा सकता है लेकिन इस समय अमेरिका में चुनावी महौल है। समय की कमी और कांग्रेस के आपसी विभाजन के कारण इस विधेयक के आगे बढ़ने की संभावना न के बराबर है। लेकिन इस बात से यह साफ है कि अमेरिका की दोनों पार्टियां भारत के साथ रिश्तों को मजबूत करने को महत्व देती हैं। ऐसे में इस बिल को अगली कांग्रेस में फिर से पेश किया जा सकता है। विधेयक में कहा गया कि कम्युनिस्ट चीन का मुकाबला करने के लिए भारत और अमेरिका की साझेदारी महत्वपूर्ण है। ऐसे में हमें अपनी साझेदारी को मजबूत करने के लिए नई दिल्ली के साथ अपने रणनीतिक, राजनयिक, आर्थिक और सैन्य संबंधों को बढ़ाने की आवश्यकता है। इसके साथ ही इस विधेयक के अनुसार, अमेरिका भारत की क्षेत्रीय अखंडता के लिए बढ़ते खतरों के जवाब में उसका समर्थन करेगा। और भारत के विरोधियों को रोकने के लिए भारत की हर संभव मदद भी करेगा इसके साथ ही वह अमेरिका रक्षा,नागरिक अंतरिक्ष के संबंध में भारत के साथ सहयोग करेगा।

पाकिस्तान को इस मामले में दो टूक कह देंगे कि यदि वह भारत के खिलाफ किसी भी तरह के आतंक में शामिल होता है तो उसको मिल रही तमाम सहायता और सुरक्षा को तत्काल प्रभाव से रोक दिया जाएगा। यह पहली बार है जब अमेरिकी कांग्रेस में इस तरीके का भारत-केंद्रित विधेयक पेश किया गया हो, जिसमें भारत को अपने नाटो सहयोगी के स्थान पर रखने और काट्सा प्रतिबंधों से छूट देने और भारत के खिलाफ आतंकवाद को बढ़ावा देने पर पाकिस्तान पर प्रतिबंध की बात कही गई हो।

इस कानून के पारित होने के बाद, यह भारत को रूसी सैन्य उपकरणों की खरीद के लिए सीएएटीएसए प्रतिबंधों से एक सीमित छूट प्रदान करेगा जो वर्तमान में भारतीय सेना द्वारा उपयोग किए जाते हैं। इसके साथ ही कांग्रेस जल्दी से जल्दी भारत की जरूरतों के हिसाब से सैन्य हथियार और सेवाओं को तैयार करने में और उनकों भारत तक पहुंचाने में अपनी भूमिका को निभाएगा। विधेयक के अनुसार यह अमेरिका के हित में हैं कि भारत के पास खतरों को रोकने की आवश्यक क्षमताएं हों। इस लिए भारत के साथ भी नाटो सहयोगियों जैसा व्यवहार करना चाहिए, जिसमें साथी देशों को हथियारों के साथ-साथ टेक्नोलॉजी भी प्रदान की जाती है। भारत के साथ एक समझौता किया जाए और उसे दो वर्षों के लिए अतिरिक्त सैन्य सामग्री देना चाहिए।

भारतवंशी कमला हैरिस को मिला ओबामा का साथ

-पत्नी मिशेल ने भी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बनने के लिए समर्थन दिया, उम्मीदवारी लगभग तय

वाशिंगटन (ईएमएस)। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा और उनकी पत्नी मिशेल ने भारतवंशी कमला हैरिस का राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए समर्थन कर दिया है। दोनों ने शुक्रवार को फोन पर कमला हैरिस को अपना समर्थन दिया। बराक ओबामा ने सोशल मीडिया पर इससे जुड़ा एक वीडियो भी पोस्ट किया है। इस वीडियो में ओबामा दंपती का समर्थन मिलने पर कमला हैरिस खुशी जता रही हैं। बाइडेन ने 22 जुलाई को रेस छोड़ने का ऐलान किया था। इसके कुछ ही देर बाद उन्होंने कमला हैरिस को डेमोक्रेटिक उम्मीदवार बनने के लिए समर्थन किया था। इसके बाद से अब तक कई डेमोक्रेटिक नेताओं ने कमला हैरिस का पार्टी के राष्ट्रपति उम्मीदवार के तौर पर समर्थन किया है।

पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अब तक दूरी बनाई हुई थी लेकिन अब जाकर उन्होंने भी कमला हैरिस के लिए हामी भर दी है। कमला हैरिस को पहले ही डेमोक्रेटिक उम्मीदवार बनने के लिए जरूरी डेलीगेट्स का समर्थन मिल चुका है। डेमोक्रेटिक पार्टी अगले महीने 1 अगस्त को राष्ट्रीय सम्मेलन बुला रही है, जिसमें कमला हैरिस को औपचारिक उम्मीदवार बनाने के लिए वोटिंग होगी।

जीत दिलाने के लिए हरसंभव कोशिश करेंगे

बराक ओबामा ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। इसमें बराक और मिशेल दोनों उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को फोन कर उन्हें अपना समर्थन दे रहे हैं। बराक ओबामा ने कमला हैरिस से कहा- मिशेल और मैं आपका समर्थन करने के लिए और आपको इस चुनाव में जीत दिलाने के और व्हाइट हाउस तक पहुंचने के लिए हरसंभव कोशिश करेंगे। इसके जवाब में कमला हैरिस ने ओबामा दंपती को उनका साथ देने के लिए धन्यवाद दिया और उनकी दशकों पुरानी दोस्ती के लिए एहसान भी जताया। कमला हैरिस ने फोन पर कहा- आपका समर्थन मेरे लिए बहुत मायने रखता है।

भारत करेगा क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी

वाशिंगटन(ईएमएस)। इस साल भारत क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी कर रहा है। इस सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन की उपस्थिति को लेकर व्हाइट हाउस ने प्रतिक्रिया दी है। व्हाइट हाउस ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन इस साल भारत में होने वाले क्वाड देशों के वार्षिक नेतृत्व शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए अभी भी प्रतिबद्ध हैं। क्वाड में ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत और अमेरिका शामिल है।

व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा संचार सलाहकारजॉन किर्बी ने कहा, हम इस साल होने वाले क्वाड शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए प्रतिबद्ध है। अभी फिलहाल कैलेंडर में इसे लेकर कुछ भी तय नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि जो बाइडन अब राष्ट्रपति चुनाव की दौड़ से बाहर हो चुके हैं। ऐसे में निश्चित रूप से उम्मीद कर सकते हैं कि कैलेंडर पर ऐसे अवसर होंगे जो पहले नहीं थे। किर्बी ने कहा, हम सभी के दिमाग में यह बात है कि उनकी विदेश नीति के एजेंडे को आगे बढ़ाने और दुनिया भर में राष्ट्रीय सुरक्षा के अवसरों के मामले में वे मौके क्या हो सकते हैं? लेकिन मेरे पास अभी बोलने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। मेरा मतलब है कि देखते रहिए, समय आने पर सब पता चल जाएगा।

हैरिस की नेतन्याहू को दो टूक.....गाजा में मासूमों की हत्या पर चुप नहीं रहूंगी

वॉशिंगटन (ईएमएस)। अमेरिका में जारी राष्ट्रपति चुनाव की सरगर्मी के बीच इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कमला हैरिस से मुलाकात की। मुलाकात में कमला हैरिस ने हमास के द्वारा बंधक बनाए गए अमेरिकी नागरिकों के मुक्त करवाने का मुद्दा उठाया। उन्होंने नेतन्याहू को दो टूक कहा कि गाजा में मासूमों की हत्या पर वे चुप नहीं रहेंगी। उन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू से कहा कि तत्काल बातचीत के जरिए युद्धविराम की जरूरत है।

नेतन्याहू से मुलाकात के बाद हैरिस ने कहा कि गाजा में युद्धविराम जरूरी है। यहां लाखों की संख्या में मासूमों की जान पर बनी है और वे भुखमरी के शिकार हैं। हैरिस ने कहा कि वह गाजा के लोगों की दिक्कतों को लेकर चुप नहीं रहेंगी। हैरिस ने कहा

वडोदरा के पास फ्लाईओवर पर ४० मीटर लंबे पुल का निर्माण पूरा

वडोदरा, २६ जुलाई।

मुंबई और अहमदाबाद के बीच चलने वाली बुलेट ट्रेन परियोजना तेजी से आगे बढ़ रही है। समय-समय पर इस परियोजना के विकास के नये विवरण सामने आते रहते हैं। वडोदरा के पास फ्लाई ओवर पर ४० मीटर लंबे पुल का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है. बुलेट ट्रेन कॉरिडोर वडोदरा के गोरवा-मधुनगर फ्लाई ओवर पर एक ऊंचे पुल के जरिए गुजर रहा है। वडोदरा से ४ कि.मी. अहमदाबाद की ओर गोरवा-महुघनगर फ्लाईओवर पर मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का एक पुल बनाया गया है। कॉरिडोर का वायाडक्ट फ्लाईओवर के ऊपर से गुजरता है। फ्लाईओवर से गुजरने वाले वाहन चालकों और पुल के निर्माण में शामिल श्रमिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए १० दिनों के ब्लॉक के भीतर पुल का निर्माण किया गया है। फ्लाईओवर पर पुल का निर्माण कार्य २३ जुलाई को पूरा हो गया था। फ्लाईओवर पर वायाडक्ट लॉन्च करने की प्रक्रिया वडोदरा सिटी पुलिस की मौजूदगी में की गई। लॉन्चिंग प्रक्रिया के दौरान, २३ जुलाई २०२४ को मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन के लिए वडोदरा में गोरवा-मधुनगर फ्लाईओवर पर ४० मीटर की सख्त बैरिकेडिंग, ट्रैफिक डायवर्जन साइन, रूट डायवर्जन नोटिस, पर्याप्त मात्रा में ट्रैफिक मार्शल और रात की रोशनी सहित सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। परियोजना। लंबा पुल पूरा हो गया है। बुलेट ट्रेन कॉरिडोर वडोदरा के गोरवा-मधुनगर फ्लाईओवर पर एक ऊंचे पुल के जरिए गुजर रहा है। यह फ्लाईओवर वडोदरा बुलेट ट्रेन स्टेशन से अहमदाबाद की ओर लगभग ४ किमी की दूरी पर स्थित है। सावधानीपूर्वक योजना और निष्पादन की सटीकता के साथ, फ्लाईओवर का शुभारंभ १० दिनों की निर्धारित अवधि के भीतर पूरा किया गया। वडोदरा शहर की ट्रैफिक पुलिस की उपस्थिति में लॉन्चिंग प्रक्रिया के दौरान सभी आवश्यक सुरक्षा सावधानियों जैसे सख्त बैरिकेडिंग, ट्रैफिक डायवर्जन संकेत, रूट डायवर्जन सूचना प्रकाशन, पर्याप्त ट्रैफिक मार्शल और रात के समय प्रकाश व्यवस्था आदि को ध्यान में रखा गया।

मुख्य लक्षण

महाद्वीपों की संख्या- १७

स्पान की लंबाई- ४० मीटर

स्तंभ की ऊंचाई- १८ मीटर

फ्लाईओवर से ऊंचाई- ८.७ मीटर

फ्लाईओवर की चौड़ाई- १६ मीटर

कुल स्पैन वजन- १०७८ मीट्रिक टन

पूर्णा नदी के उफान पर आने से नवसारी शहर जलमग्न हो गया

नवसारी, २६ जुलाई।

ऊपरी इलाकों में मूसलाधार बारिश के कारण पूर्णा नदी उग्र नदी में तब्दील हो गयी है। पूर्णा नदी का खतरे का स्तर २३ फीट है जो फिलहाल २८ फीट के आसपास बह रही है। इसके चलते नवसारी शहर के १० इलाकों में बाढ़ का पानी भर जाने से लोग अपना घर छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। शहर के १० इलाकों में घर हों या दुकानें हर जगह ५ से ७ फीट तक पानी देखा जा रहा है। पूर्णा नदी में आई बाढ़ के कारण नवसारी-सूरत हाईवे समेत कई अन्य सड़कें बंद हो गई हैं। सूरत, वडोदरा के बाद अब नवसारी में पानी बम है।

नवसारी जिले में अभी भारी बारिश नहीं हुई है, लेकिन डांग समेत ऊपरी इलाकों में भारी बारिश के कारण नवसारी जिले में आफत पहुंच गई है। पूना नदी का पानी शहर के गढ़ेवान, मोरलो, पुरानी मच्छी मार्केट, कमेला दरवाजा, रंगून नगर, मिथिला नगरी, शांतादेवी रोड और अन्य इलाकों में भर गया है। इसलिए हजारों लोग विस्थापित हो गए हैं। नवसारी की कई सोसायटियों में पानी भर गया है। शहर के कालियावाड़ी इलाके में स्थित शांतिवन सोसायटी में पानी भरने के कारण कई लोग घर की पहली मंजिल पर रहने को मजबूर हो गए हैं।

पूर्णा नदी का जलस्तर बढ़ने की आशंका को देखते हुए सिस्टम ने लोगों से सहयोग की अपील की है। नवसारी-सूरत को जोड़ने वाले राज्य राजमार्ग पर भी पूर्णा नदी का पानी लौट आया है। इसलिए इस स्टेट हाईवे को बंद कर दिया गया है और पुलिस की व्यवस्था कर दी गई है। फिलहाल नवसारी शहर का सूरत से संपर्क बंद कर दिया गया है। नवसारी में बाढ़ की स्थिति को लेकर जिला कलेक्टर क्षिप्रा अग्रे ने कहा कि पूर्णा नदी का खतरनाक स्तर पार हो गया है। नवसारी शहर में २२०० लोगों को आश्रय गृहों में स्थानांतरित किया गया है। इस शेल्टर होम में लोगों की सुरक्षा के लिए १५ मेडिकल टीमें तैनात हैं। १० गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित अस्पताल पहुंचाया गया है। शहर में बाढ़ प्रभावित १७ सड़कें बंद कर दी गई हैं।

सूरत के साथ-साथ नवसारी और तापी जिलों में भी भारी बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। कई इलाकों में पानी भर गया है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। उकाई बांध से पानी छोड़े जाने का निर्णय कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे कि बांध का जलस्तर, बारिश की तीव्रता, और नदी का जलस्तर। बांध प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर रख रहा है और आवश्यकता पड़ने पर पानी छोड़े जाने का निर्णय लिया जाएगा।

वडोदरा में बंद इमारत की दीवार लोगों के बीच गिर गई

वडोदरा, २६ जुलाई।

वडोदरा शहर के कालूपुरा इम्प्रूवमेंट स्टोर के पास एक लकड़ी की क्लैपबोर्ड बिल्डिंग की दीवार गिरने से लोगों में हड़कंप मच गया। हालांकि, किसी के मौजूद न होने से बड़ा हादसा टल गया। वडोदरा शहर में मेघराजा की भारी बारिश के कारण निचले इलाकों में बारिश का पानी भर गया है। वहीं, बारिश में जर्जर मकान, स्लैब, पेड़, होर्डिंग्स गिरने की भी घटनाएं हो रही है। तभी दोपहर करीब १२:२५ बजे कालूपुरा सुधराई स्टोर के पास लिंबडी पालिया में एक बंद मकान की दीवार ढह गई।

दीवारटूटनेकीआवाजसे स्थानीय लोग डर गए और घर से बाहर निकल गए। सौभाग्य से, उन्होंने राहत की सांस ली कि कोई हताहत नहीं हुआ। वडोदरा में बारिश और तेज हवाओं के कारण मकान गिरने, होर्डिंग गिरने के मामले लगातार देखने को मिल रहे हैं। हाल ही में सलाटवाड़ा में देर रात एक जर्जर मकान गिरने से सात लोग फंस गए थे, जबकि एक बुजुर्ग व्यक्तिके फंसे होने की सूचना देने के लिए फायर ब्रिगेड ने देर रात तक काम किया। शुक्रवार को करीब १२:२५ बजे जसिंगभाई मकवाणा ने सिटी कमांड एंड कंट्रोल रूम को सूचना दी कि सुधराई स्टोर के सामने की इमारत की दीवार गिर गई है। कॉल मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और मलबा हटाने का काम किया।

गुजरात के भरूच में पलटी निजी कंपनी की बस

भरूच, २६ जुलाई।

गुजरात के भरूच में एक लग्जरी बस पलटने की घटना सामने आई है। बस में निजी कंपनी का स्टॉफ सवार था। रात के अंधेरे में हुई घटना में लोगों को निकालने के लिए बस के शीशे तोड़ने पड़े। भरूच में यह घटना ऐसे वक्तपर घटी जब इलाके में भारी बारिश हो रही थी। निजी कंपनी की बस पलटने की सूचना पर प्रशासन में हड़कंप मच गया, हालांकि बस के अंदर मौजूद स्टॉफ को शीशे तोड़कर सुरक्षित बाहर निकाला गया। कंपनी की बस पलटने की सूचना में प्रबंधन में भी हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंचे पुलिस-प्रशासन ने स्थिति को संभाला और फिर बस को रेस्क्यू कराया गया।

जानकारी के अनुसार भरूच जिले के दहेज में एसआरएफ कंपनी की बस पलटने से हादसा हुआ। यह घटना बुधवार की रात को हुई। कंपनी की लग्जरी बस में नाइट शिफ्ट के लिए कर्मचारियों को ले जाया जा रहा था। अटाली गांव के पास स्थित वैभव होटल के पास लग्जरी बस पलट गई। मजदूरों को बचाने के लिए बस के शीशे तोड़े गए और फिर उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला गया। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि ड्राइवर की लापरवाही से यह हादसा हुआ। इसमें कंपनी के कर्मचारियों की जान पर बन आई। गनीमत यह रही कि इस हादसे में मामली चोट के अलग कोई जनहानि नहीं हुई। मध्य गुजरात में आने वाले भरूच जिले में पिछले दो दिनों से काफी ज्यादा बारिश हो रही है। भारी बारिश के चलते भरूच के कुछ इलाकों में भीषण बाढ़ की स्थिति खड़ी हो गई है। निचले इलाकों में पानी भर गया है। काफी लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया है।

गुजरात कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं को सेक्टर, मंडल, बूथ प्रबंधन की तालीम देगी

अहमदाबाद (ईएमएस) गुजरात कांग्रेस ने दाहोद और महीसागर जिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं को सेक्टर, मंडल और बूथ प्रबंधन के लिए तालीमबद्ध करेगी इसके लिए गुजरात कांग्रेस ने जिला स्तर पर 'कांग्रेस संकल्प शिविर' का आयोजन किया है इसके अंतर्गत 27 जुलाई 2024 को दोपहर 12 बजे और 28 जुलाई2024 को दोपहर 12-00 बजे महिसागर तेजा होटल, गोधरा हाईवे रोड, लुनावाड़ा में आयोजित होने वाले कांग्रेस संकल्प शिविर का आयोजन किया गया है इसका उदघाटन अखिल भारतीय कांग्रेस के वरिष्ठ महासचिव और गुजरात कांग्रेस संगठन के प्रभारी मुकुल वासनिक करेगी संकल्प शिविर में गुजरात विधानसभा कांग्रेस दल के नेता अमित चावड़ा, उपनेता शैलेश परमार, एआईसीसी मंत्री और मध्य गुजरात संभाग प्रभारी उषा नायडू उपस्थित रहेंगे और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। दाहोद और महिसागर जिले में होने वाले कांग्रेस संकल्प शिविर में कांग्रेस पार्टी की विचारधारा, भारत निर्माण का इतिहास और सेक्टर-मंडल और बूथ प्रबंधन सहित विषयों पर विशेषज्ञ प्रशिक्षण देंगे दाहोद और महिसागर में आयोजित होने वाले प्रशिक्षण शिविर में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और विधायक, पूर्व जिला अध्यक्ष, प्रत्येक तहसील के अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, जिला और तहसील विपक्षी नेता, पूर्व विपक्षी नेता, जिला और तहसील निर्वाचित सदस्य, जिला और तहसील कांग्रेस के सभी कार्यकारी पदाधिकारी, सभी जिला और तहसील फैन्टल सेल, किसान सेल, बख्शी सेल, अल्पसंख्यक सेल, एससी सेल, एसटी सेल, जिला और तहसील सेवादल, महिला कांग्रेस, युवा कांग्रेस, एनएसयूआई कांग्रेस, सभी अध्यक्ष, साथ ही सभी कार्यकारी पदाधिकारी, स्थानीय नगर पालिकाओं के पूर्व अध्यक्ष, साथ ही नगरसेवक, वरिष्ठ नेता, कार्यकर्ता मित्र, कांग्रेस शिविर में संकल्प शिविर उपस्थित रहेंगे।

गुजरात सरकार ने जीवन रक्षक दवाइयों की सूची में की वृद्धि, अब इतनी दवाइयां मिलेंगी मुफ्त

अहमदाबाद (ईएमएस) राज्य सरकार ने जीवन रक्षक स्वास्थ्य दवाइयों की आवश्यक सूची (ईडीएल) 2024-25 में 665 नई दवाएं शामिल की हैं। पहले राज्य सरकार की आवश्यक औषधि सूची में 717 दवाइयां थीं, जो अब वर्ष 2024-25 में बढ़कर 1382 हो गयी हैं। राज्य के हर मरीज को सर्वोत्तम इलाज और गुणवत्तायुक्त दवाइयां उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। ये दवाएं राज्य के सभी स्वास्थ्य केंद्रों, उपकेंद्रों से लेकर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के सिविल अस्पतालों तक मुफ्त उपलब्ध होंगी।

मानसून के दौरान हेपेटाइटिस ए से मुकाबला: जोखिम और रोकथाम रणनीतियाँ

वडोदरा, 26/07/2024: जैसे-जैसे मानसून का मौसम शुरू होता है, अधिकांश भारतीय राज्य हेपेटाइटिस ए के मामलों में वृद्धि का सामना करते हैं, जिससे स्वास्थ्य अधिकारियों के बीच सतर्कता बढ़ गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की 2024 ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट एक परेशान करने वाली प्रवृत्ति का खुलासा करती है, जिसमें वायरल हेपेटाइटिस अब विश्व स्तर पर मृत्यु का दूसरा प्रमुख संक्रामक कारण बन गया है, जो टीबी के समान, सालाना 1.3 करोड़ लोगों की जान लेता है। हेपेटाइटिस ए के खिलाफ टीकाकरण की दृढ़ता से सलाह दी जाती है, जो वायरस के खिलाफ मजबूत, दीर्घकालिक सुरक्षा प्रदान करता है। डॉ. तुषार शाह, सलाहकार और निदेशक, नैदानिक अनुसंधान विभाग, काशीबेन गोर्धनदास पटेल चिल्ड्रन हॉस्पिटल, वडोदरा कहते हैं कि ठहेपेटाइटिस ए से निपटने में रोकथाम महत्वपूर्ण है, और टीकाकरण हमारा सबसे प्रभावी उपकरण है।हेपेटाइटिस ए का टीका केवल एक खुराक के साथ दीर्घकालिक प्रतिरक्षा प्रदान करता है, जिससे सुरक्षा प्रक्रिया सरल हो जाती है। शरीर की प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को उत्तेजित करके, टीका हेपेटाइटिस ए वायरस के भविष्य के जोखिम से सुरक्षा सुनिश्चित करता है।

मोढवाडिया की भारी बारिश से हुए नुकसान का सर्वे करवा किसानों को सहायता देने की मांग

अहमदाबाद (ईएमएस) पोरबंदर के विधायक अर्जुन मोढवाडिया ने मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल और कृषि मंत्री राघवजी पटेल को पत्र लिखकर पोरबंदर जिले में भारी बारिश और बाढ़ के कारण फसल के नुकसान और खेत के कटाव के संबंध में तत्काल सर्वेक्षण करने और किसानों को सहायता देने का अनुरोध किया है। भारी बारिश और बाढ़ के कारण किसानों की फसलों को हुए नुकसान का सर्वेक्षण राज्य कृषि विभाग के माध्यम से कराया जाना चाहिए और राज्य सरकार की मुख्यमंत्री किसान योजना और एसडीआरएफ योजना के तहत सहायता दी जानी चाहिए साथ ही बाढ़ की स्थिति के कारण किसानों के खेतों में हो रहे कटाव का सर्वेक्षण कराकर खेतों को समतल करने में सहायता दी जाए अर्जुन मोढवाडिया ने कहा कि पोरबंदर जिले में भारी बारिश और बाढ़ से किसानों की फसल बर्बाद हो गई है और बड़े पैमाने पर खेत का कटाव हो गया है। जिसे देखते हुए फसल के नुकसान और खेत के कटाव के संबंध में तत्काल सर्वेक्षण करने और किसानों को सहायता दी जानी चाहिए इस संदर्भ में मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल और कृषि मंत्री राघवजी पटेल को लिखे पत्र में अर्जुन मोढवाडिया ने कहा है कि पोरबंदर जिले में किसानों द्वारा लगाई गई मूंगफली, कपास, सोयाबीन जैसी फसलों को भारी नुकसान हुआ है। इसके अलावा भारी बाढ़ के कारण किसानों के खेत बह गये हैं अर्जुन मोढवाडिया ने आगे कहा है कि इस वर्ष घेड़ क्षेत्र में भी कई गांवों में मूंगफली लगाई गई थी इन बागानों का एक बड़ा हिस्सा नष्ट हो गया जिससे किसानों को असहनीय क्षति हुई। इस स्थिति में किसानों की मदद के लिए राज्य सरकार की मुख्यमंत्री किसान योजना और एसडीआरएफ योजना के तहत सहायता प्रदान करने के लिए राज्य कृषि विभाग के माध्यम से किसानों की फसलों की क्षति का सर्वेक्षण कराया जाना चाहिए और खेतों को समतल करने में मदद की जानी चाहिए।

मुख्यमंत्री ने 'एक पेड़ मां के नाम' के अंतर्गत राज्यव्यापी अर्बन फॉरेस्ट अभियान का गांधीनगर से शुभारंभ किया

गांधीनगर (ईएमएस) प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा प्रेरित देशव्यापी महाअभियान 'एक पेड़ मां के नाम' को शहरी क्षेत्रों तक पहुंचाने के उम्दा आशय से पूरे राज्य में 31 अगस्त तक अर्बन फॉरेस्ट विकसित करने का अभियान आयोजित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने शुक्रवार को गांधीनगर महानगर पालिका क्षेत्र में स्थित कोबा इलाके में बरगद का पौधा लगाकर राज्यव्यापी अर्बन फॉरेस्ट अभियान का शुभारंभ किया। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 5 जून, 2024 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान चलाने का आह्वान किया था। पर्यावरण को बचाने के प्रधानमंत्री के इस उम्दा दृष्टिकोण को मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में ग्रामीण के साथ-साथ शहरी क्षेत्रों तक ले जाने के लिए पूरे राज्य में आगामी 31 अगस्त, 2024 तक अर्बन फॉरेस्ट अभियान का आयोजन किया गया है। अर्बन फॉरेस्ट अभियान के अंतर्गत राज्य के शहरों में वन एवं वृक्ष क्षेत्र को बढ़ाने के लक्ष्य के साथ राज्य की महानगर पालिकाओं, 157 नगर पालिकाओं और सभी 165 शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) में 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के अंतर्गत अर्बन फॉरेस्ट अभियान आयोजित किया गया है। इसके अंतर्गत सरकार के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण के व्यक्तिगत दायित्व के विषय में लोगों के बीच और अधिक जागरूकता पैदा करने के लिए नागरिकों, गणमान्य लोगों और विभिन्न संस्थानों की सहभागिता से शहरी वनीकरण, मियावाकी वन और ग्रीन स्पेस से संबंधित अन्य कार्यक्रम सभी शहरों में आयोजित किए जाएंगे। 'एक पेड़ मां के नाम' विशेष महाअभियान के अंतर्गत महानगर पालिका और नगर पालिका क्षेत्र में हर वॉर्ड और जोन में विशेष स्थान पर वृक्षारोपण किया जाएगा। रोपे गए पौधों की देखभाल के लिए इस स्थान के चारों ओर सुरक्षा के लिए बाड़ या दीवार का निर्माण भी किया जाएगा। कोबा में अर्बन फॉरेस्ट अभियान के शुभारंभ अवसर पर उपस्थित सभी महानुभावों ने एक-एक पौधा लगाया। कोबा में 4700 वर्ग मीटर से अधिक के क्षेत्रफल वाले भूखंड में अर्बन फॉरेस्ट का निर्माण होगा। यहां नीम, आम, इमली, बोरसली और आंवला जैसे कुल 1500 पौधे रोपे जाएंगे। इस अवसर पर गांधीनगर महानगर पालिका की महापौर श्रीमती मीराबेन पटेल, गांधीनगर (द) के विधायक अल्पेश ठाकोर, गांधीनगर (उ) की विधायक श्रीमती रीटाबेन पटेल, उप महापौर नटवरजी ठाकोर, जिला कलेक्टर मेहुल दवे, मनपा आयुक्त जे.एन. वाघेला सहित कई गणमान्य व्यक्ति और बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे।

मानसून के दौरान हेपेटाइटिस ए से मुकाबला: जोखिम और रोकथाम रणनीतियाँ

वडोदरा, 26/07/2024: जैसे-जैसे मानसून का मौसम शुरू होता है, अधिकांश भारतीय राज्य हेपेटाइटिस ए के मामलों में वृद्धि का सामना करते हैं, जिससे स्वास्थ्य अधिकारियों के बीच सतर्कता बढ़ गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की 2024 ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट एक परेशान करने वाली प्रवृत्ति का खुलासा करती है, जिसमें वायरल हेपेटाइटिस अब विश्व स्तर पर मृत्यु का दूसरा प्रमुख संक्रामक कारणबनगया है,जो टीबी के समान,सालाना 1.3 करोड़ लोगों की जान लेता है। हेपेटाइटिस ए के खिलाफ टीकाकरण की दृढ़ता से सलाह दी जाती है, जो वायरस के खिलाफ मजबूत, दीर्घकालिक सुरक्षा प्रदान करता है। डॉ. तुषार शाह, सलाहकार और निदेशक, नैदानिक अनुसंधान विभाग, काशीबेन गोर्धनदास पटेल चिल्ड्रन हॉस्पिटल, वडोदरा कहते हैं कि ठहेपेटाइटिस ए से निपटने में रोकथाम महत्वपूर्ण है, और टीकाकरण हमारा सबसे प्रभावी उपकरण है।हेपेटाइटिस ए का टीका केवल एक खुराक के साथ दीर्घकालिक प्रतिरक्षा प्रदान करता है, जिससे सुरक्षा प्रक्रिया सरल हो जाती है। शरीर की प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को उत्तेजित करके, टीका हेपेटाइटिस ए वायरस के भविष्य के जोखिम से सुरक्षा सुनिश्चित करता है।

आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेडने एंथे 2024 के लांच के साथ एंथे के 15 गौरवशाली वर्षों का जश्न मनाया

अपनी प्रमुख छात्रवृत्ति परीक्षा एंथे के गौरवशाली 15वर्षों को पूरा करते हुए, परीक्षण तैयारी सेवाओं में राष्ट्रीय अग्रणी, आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड ने गर्व से बहुप्रतीक्षित आकाश नेशनल टैलेंट हंट एग्जाम (एंथे) 2024 के लांच की घोषणा की है। एंथे लोकप्रिय और सबसे अधिक मांगवाली परीक्षा है, जो सातवीं – बारहवीं कक्षा के छात्रों को महत्वपूर्ण नकद पुरस्कारों के साथ 100 प्रतिशत तक छात्रवृत्ति0 अर्जित करने का मौका देती है, जिससे उन्हें चिकित्सा या इंजीनियरिंग में एक सफल करियर के अपने सपनों को हासिल करने में मदद मिलती है।इस वर्ष, इसे विशेष और रोमांचक बनाने के लिए इसमें पांच उत्कृष्ट छात्रों के लिए फ्लोरिडा, यूएसए में कैनेडी स्पेससेंटर की पांच दिवसीयपूर्ण- खर्च-भुगतान यात्रा शामिल की गई है। फ्लोरिडा में स्थित जॉन एफ कैनेडी स्पेस सेंटर, संयुक्त राज्य अमेरिका में नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एड मिनिस्ट्रेशन (नासा) के दस फील्डसेंटरों में से एक है।आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड के सीईओ और एमडी श्री दीपक मेहरोत्रा ने कहा, ''आकाश नेशनल टैलेंट हंट एग्जाम (एंथे) ने अनगिनत छात्रों की आकांक्षाओं और क्षमताओं के बीच अंतर को पाटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।एंथे 2024 का आयोजन 19 से 27 अक्टूबर 2024 के बीच ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में, भारत के 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में होगा, 100 प्रतिशत तक की छात्रवृत्तियों के अलावा, शीर्ष स्कोरर्स को नकद पुरस्कार भी प्रदान किया जाएगा।थे ऑफलाइन परीक्षा 20 और 27 अक्टूबर 2024 को आकाश इंस्टीटयूट के सभी 315+ केंद्रों पर सुबह1 0:30 बजे से 11:30 बजे तक आयोजित की जाएगी, जबकि ऑनलाइन परीक्षा 19 से 27अक्टूबर 2024 के बीच किसी भी समय लि यादी जा सकती है। छात्र अपने अनुकूल समय में एक घंटे का स्लॉट चुन सकते हैं।एंथे 2024 के लिए रजिस्ट्रेशन फार्म जमा करने की अंतिम तिथि ऑनलाइन परीक्षा के प्रारंभ से तीन दिन पहले और ऑफलाइन परीक्षा के प्रारंभ से सात दिन पहले है। परीक्षा शुल्क दोनों ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड के लिए 200 रूपये फीस निर्धारित की गई है। छात्र 15 अगस्त 2024 से पहले पंजीकरण शुल्क पर फ्लैट 50 प्रतिशत की छूट भी प्राप्त कर सकते हैं।एंथे 2024 के परिणाम 8 नवंबर 2024 को कक्षा 10के छात्रों के लिए, 13 नवंबर 2024 को कक्षा 7 से 9 के लिए, और 16 नवंबर 2024 को कक्षा 11 और 12 के छात्रों के लिए घोषित किए जाएंगे।

पश्चिम रेलवे की तरफ से चलेंगी छह जोड़ी गणपति स्पेशल ट्रेनें

मुंबई, २६ जुलाई।

पश्चिम रेलवे ने समर और मानसून स्पेशल ट्रेनों के बाद अब गणपति महोत्सव के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान किया है। पश्चिम रेलवे गणपति महोत्सव २०२४ के दौरान अतिरिक्त भीड़ को नियंत्रित करने के उद्देश्य से मुंबई सेंट्रल-ठोकुर, मुंबई सेंट्रल - सावंतवाड़ी रोड, बांद्रा टर्मिनस-कुडाल, अहमदाबाद-कुडाल, विश्वामित्री-कुडाल और अहमदाबाद-मंगलुरु स्टेशनों के बीच विशेष किराए पर स्पेशल ट्रेनें चलाएगी। पश्चिम रेलवे के चीफ पीआरओ विनीत अभिषेक ने कहा कि कि ट्रेन संख्या ०९००१, ०९० ०९, ०९०१५, ०९४१२, ०९१५० और ०९४२४ की बुकिंग २८ जुलाई, २०२४ से सभी पीआरएस काउंटरों और आईआरसीटीसी वेबसाइट पर शुरू होगी।

१.ट्रेन संख्या ०९००१ मुंबई सेंट्रल- ठोकुर साप्ताहिक स्पेशल हर मंगलवार को मुंबई सेंट्रल से १२.०० बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन ०८.५० बजे ठोकुर पहुँचेगी। यह ट्रेन ०३ से १७ सितंबर, २०२४ तक चलेगी। इसी तरह, ट्रेन संख्या ०९००२ ठोकुर -मुंबई सेंट्रल साप्ताहिक स्पेशल हर बुधवार को ठोकुर से ११.०० बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन ०७.०५ बजे मुंबई सेंट्रल पहुंचेगी। यह ट्रेन ०४ से १८ सितंबर, २०२४ तक चलेगी। २. ट्रेन संख्या ०९००९ मुंबई सेंट्रल - सावंतवाड़ी रोड स्पेशल प्रतिदिन (मंगलवार को छोड़कर) मुंबई सेंट्रल से १२.०० बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन ०२.३० बजे सावंतवाड़ी रोड पहुँचेगी। यह ट्रेन २ से १६ सितंबर, २०२४ तक चलेगी। इसी तरह, ट्रेन संख्या ०९०१० सावंतवाड़ी रोड - मुंबई सेंट्रल स्पेशल प्रतिदिन (बुधवार को छोड़कर) सावंतवाड़ी रोड से ०४.५० बजे प्रस्थान करेगी और उसी दिन २०.१० बजे मुंबई सेंट्रल पहुंचेगी। यह ट्रेन ३ से १७ सितंबर, २०२४ तक चलेगी। ३. ट्रेन संख्या ०९०१५ बांद्रा टर्मिनस- कुडाल साप्ताहिक स्पेशल प्रत्येक गुरुवार को बांद्रा टर्मिनस से १४.४० बजे प्रस्थान करेगी और अगलेदिन०३.३०बजेकुडाल पहुँचेगी। यह ट्रेन ०५ से १९ सितंबर, २०२४तकचलेगी। इसी तरह, ट्रेन संख्या ०९०१६कुडाल -बांद्रा टर्मिनस साप्ताहिक स्पेशल प्रत्येक शुक्रवार को कुडाल से ०४.३० बजे प्रस्थान करेगी और उसी दिन १८.१५ बजे बांद्रा टर्मिनस पहुंचेगी। यह ट्रेन ०६ से २० सितंबर, २०२४ तक चलेगी। यह ट्रेन दोनों दिशाओं में बोरीवली, वसई रोड, पनवेल, रोहा, मानगांव, वीर, करंजाडी, खेड़, चिपलून, सावर्डा, अरवली रोड, संगमेश्वर रोड, रत्नागिरी, आडवली, विलवडे, राजापुर रोड, वैभववाड़ी रोड, नांदगांव रोड, कणकवली और सिंधुदुर्ग स्टेशनों पर रुकेगी। इस ट्रेन में सामान्य द्वितीय श्रेणी सीटिंग कोच होंगे।

४. ट्रेन सं. ०९४१२/०९४११ अहमदाबाद - कुडाल स्पेशल प्रत्येक सोमवार को विश्वामित्री से १०.०० बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन ०३.३० बजे कुडाल पहुंचेगी। यह ट्रेन ०२ से १६ सितंबर, २०२४ तक चलेगी। इसी तरह, ट्रेन संख्या ०९१४९ कुडाल- विश्वामित्री साप्ताहिक स्पेशल प्रत्येक मंगलवार को कुडा ल से ०४. ३० बजे प्रस्थान करेगी और उसी दिन २२. ०० बजे विश्वामित्री पहुंचेगी। यह ट्रेन ०३से १७ सितंबर, २०२४ कचलेगी।

६.ट्रेन संख्या ०९४२४ अहमदाबाद- मंगलुरु साप्ताहिकस्पेशल प्रत्येकशुक्रवारकोअहमदाबादसे १६.०० बजेप्रस्थान करेगी और अगले दिन १९.४५ बजे मंगलुरु पहुँचेगी।

पश्चिम रेलवे - वडोदरा मंडल

विभिन्न सिग्नलींग कार्य

निविदा सूचना सं. S&T/BRC/24-25/17/SIG

दिनांक : 24-07-2024

भारत के राष्ट्रपति के लिए एवं उनकी ओर से कार्यरत वरिष्ठ डीएसटीई/वडोदरा निविदा सं. SandT_BRC_24-25_17_SIG के लिए ई-निविदाएं आमंत्रित करते हैं। बिडर्स बिड बंद होने की तारीख और समय तक उनके प्रमाणित/संशोधित जमा कराने को समर्थ रहेंगे, यह निविदा के सामने मेन्युअल प्रस्तावों की अनुमति नहीं है एवं ऐसे किसी भी प्रकार के मेन्युअल प्रस्तावों को ध्यान में नहीं लिया जायेगा। **(1) कार्य का नाम उसके स्थान सहित:** वडोदरा मंडल में तीन वर्षों की समयावधि के लिये ADSTE के अनुभाग अनुसार सिग्नलींग गीयर्स के रखरखाव एवं मरम्मत के संबंध में वडोदरा मंडल में सहायक मंडल संकेत व दूरसंचार अभियंता (भरूच-I) और सहायक मंडल संकेत व दूरसंचार अभियंता (भरूच-II) के अनुभाग में तीन वर्षों की समयावधि के लिये सिग्नलींग गीयर्स का रखरखाव एवं मरम्मत करने का कार्य। **(2) कार्य की अनुमानित लागत:** ₹ 1,24,92,406.45 **(3) जमा कराने की बयाना राशी:** ₹ 2,12,500.00 **(4) ई-निविदा जमा कराने एवं ई-निविदा खोलने की तिथि एवं समय:** दिनांक 16/08/2024 को 15:00 बजे एवं दिनांक 16/08/2024 को 15:30 बजे निविदा खोली जाएगी **(5) वेबसाईट का विवरण एवं नोटीस का स्थान जहाँ से विवरण देखे जा सकते हैं आदि: http://www.ireps.gov.in** वरिष्ठ मंडल संकेत व दुरसंचार अभियंता, द्वितीय तल, एनेक्ष बिल्डींग, म.रे.प्र. कार्यालय, पश्चिम रेलवे, प्रतापनगर, वडोदरा-390 004.

BRC-136

हमें फोलो करें: twitter.com/WesternRly

मुंबई मंडल में भारी बारिश एवं जल भराव के कारण कुछ ट्रेनें प्रभावित

अहमदाबाद (ईएमएस) पश्चिम रेलवे के मुंबई मंडल पर भारी बारिश के कारण चिंचपाडा-कोलदा स्टेशनों के बीच जल भराव के चलते कुछ ट्रेनें प्रभावित हुई है। जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

निरस्त ट्रेनें :26 जुलाई 2024 की ट्रेन संख्या 09315 वडोदरा-अहमदाबाद मेमू,

26 जुलाई 2024 की ट्रेन संख्या 09274 अहमदाबाद-आणंद मेमू,

रेगुलेट ट्रेनें,

24 जुलाई 2024 को बरौनी से चलने वाली ट्रेन संख्या 19484 बरौनी-अहमदाबाद एक्सप्रेस नंदूरबार,

स्टेशन पर रेगुलेट होगी।

परिवर्तित मार्ग से चलने वाली ट्रेनें

26जुलाई 2024 की ट्रेन संख्या 12833 अहमदाबाद-हावड़ा एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग वाया वडोदरा-रतलाम संत हिरदारम नगर-इटारसी-नागपुर के रास्ते चलेगी। 26 जुलाई 2024 की ट्रेन संख्या 19483 अहमदाबाद-बरौनी एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग वाया वडोदरा-रतलाम-संत हिरदाराम नगर के रास्ते चलेगी। 25 जुलाई 2024 की ट्रेन संख्या 20824 अहमदाबाद-पुरी एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग वाया वडोदरा-रतलाम-संत हिरदाराम नगर-भोपाल-इटारसी-नागपुर के रास्ते चलेगी। 25 जुलाई 2024 की ट्रेन संख्या 12656 चेन्नई सेंट्रल-अहमदाबाद नवजीवन एक्सप